Kamal.Sandesh kamalsandesh.org KamalSandesh

कमल संदेश

वर्ष-17, अंक-04 16-28 फरवरी, 2022 (पाक्षिक) ₹20

'उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से योगी आदित्यनाथ सरकार पुनः बनने जा रही है'

केन्द्रीय बजट 2022-23

₹48,000 करोड़
आवास क्षेत्र

₹60,000 करोड़
जल जीवन मिशन

राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में
25,000 किलोमीटर
का विस्तार

₹7.5 लाख करोड़
का पूंजीगत व्यय

400 उत्कृष्ट
'वंदे भारत' रेलगाड़ियों
का निर्माण

60 लाख
नये रोजगार

100 नए
मल्टीमॉडल टर्मिनल

आर्थिक समीक्षा 2021-22 | आत्मनिर्भरता का बजट | विधानसभा चुनावों पर विशेष

नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज 'तिरंगा' का ध्वजारोहण करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

कोंच (उत्तर प्रदेश) में एक जनसभा के दौरान जनाभिवादन स्वीकार करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

कौशांबी (उत्तर प्रदेश) में उप्र के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद एक रोड शो के दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

लोनी (गाजियाबाद), उत्तर प्रदेश में एक जनसभा के दौरान जनाभिवादन स्वीकार करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह व अन्य वरिष्ठ भाजपा नेतागण

गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नामांकन पत्र दाखिल करते समय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

आगरा ग्रामीण (उत्तर प्रदेश) में एक जनसभा के दौरान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 नए भारत का 'आत्मनिर्भर बजट'

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को संसद में केन्द्रीय बजट 2022-23 प्रस्तुत करते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो दुनिया की समस्त बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है। कोविड महामारी के प्रतिकूल...

16 एक तरफ भाजपा है जिसके पास विजन है, दूसरी तरफ अहंकार से भरे 'नकली समाजवादी' हैं : नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 31 जनवरी...

18 'विपक्ष भले कितने ही साजिश क्यों न रच ले, भारी बहुमत से योगी आदित्यनाथ सरकार पुनः बनने जा रही है'

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश...

20 भाजपा सरकार में विकास जन-जन तक पहुंचा : अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने 27 जनवरी, 2022 को...

27 'हम पंजाब की शांति, सुरक्षा और समृद्धि चाहते हैं'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 24 जनवरी 2022 को भाजपा के केन्द्रीय कार्यालय में आयोजित...

वैचारिकी

सिद्धांत और नीतियां / **पं. दीनदयाल उपाध्याय** 24

श्रद्धांजलि

नहीं रहीं भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर 26

चंदूपतला जंग रेड्डी का निधन 26

लेख

भविष्योन्मुखी बजट / **रघुवर दास** 30

उत्तर प्रदेश में भाजपा की राजनीतिक यात्रा : एक नजर / **राम प्रसाद त्रिपाठी** 31

युवाओं का बजट / **विकास आनन्द** 33

अन्य

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख नए रोजगार का सृजन होगा 14

'डबल इंजन की सरकार आने से चीजें कैसे बदलती हैं, इसका बहुत बड़ा उदाहरण ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन है' 17

आर्थिक समीक्षा 2021-22 22

राष्ट्रपति अभिभाषण 28

लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हुई चर्चा पर प्रधानमंत्री का उत्तर 29

श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची 'स्टैच्यू ऑफ इक्वैलिटी' राष्ट्र को समर्पित 34

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

एक तरफ भाजपा है, जिसके पास विकास का स्पष्ट विजन है। वहीं, दूसरी तरफ किसी भी कीमत पर सत्ता पाने का सपना देख रहे नकली समाजवादी हैं, जिनके पास विजन के नाम पर सिर्फ विरोध, गुस्सा और आक्रोश है।

जगत प्रकाश नड्डा

जब केदारनाथ में त्रासदी हुई थी तब मोदीजी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तब उन्होंने कहा था कि केदारनाथ मुझे दे दो मैं सुधार दूंगा। उस समय की उत्तराखंड की सरकार ने नहीं सुनी, भगवान ने सुनी और मोदीजी को प्रधानमंत्री बनाया और उन्होंने केदारनाथ और उत्तराखंड के विकास कार्य को आगे बढ़ाया।

अमित शाह

उत्तर प्रदेश का चुनाव दो विचारधाराओं के बीच चुनाव है। एक ओर सपा है जो अपने परिवार के लिए और माफियाओं को संरक्षण देने के लिए चुनाव लड़ रही है तो दूसरी तरफ भाजपा है जो उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए और माफियाओं को खत्म करने के लिए चुनाव लड़ रही है।

राजनाथ सिंह

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के पांच वर्षों में विकास और सुशासन का नया दौर देखने को मिला है। विकास को मज़बूती देने का काम केवल भाजपा सरकारें ही कर सकती हैं।

बी.एल. संतोष

2 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपग्रेड किया जाएगा, 8.7 करोड़ परिवारों को 'हर घर जल' की सुविधा मिलेगी, जिसमें से 5.5 करोड़ को नल से पानी मिलेगा। 2022-23 में 3.8 करोड़ और परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए 50,000 करोड़ रुपये का आवंटन। पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख लाभार्थियों की पहचान की गई है, जिसके लिए 40,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

नितिन गडकरी

हमारी सरकार का जोर उचित कनेक्टिविटी पर है और इन्फ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों का हल गति शक्ति के माध्यम से निकाला जा सकता है। 'पीएम गतिशक्ति' इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास और समृद्धि की राह पर आगे बढ़ना जारी रखेगा।

कमल संदेश परिवार की ओर से
सुधी पाठकों को
गुरु रविदास जयंती (16 फरवरी)
की हार्दिक शुभकामनाएं!

संपादकीय

आत्मनिर्भरता का बजट

बजट 2022-23 लंबे समय से चल रहे कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बीच एक ऐसे उभरते हुए भारत की आकांक्षाएं प्रस्तुत करता है जो दृढ़ संकल्पशक्ति के बल पर नित नई ऊंचाइयां छूना चाहता है। यह एक ऐसा बजट है जो न केवल 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए बनाई गई नीतियों को मजबूत आधार दे रहा है, बल्कि 'आत्मनिर्भरता' की एक मजबूत नींव डाल रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की भविष्योन्मुखी नीतियों को मूर्त रूप देने वाला यह बजट विकास की गति तीव्र करेगा, रोजगार को बढ़ावा देगा एवं गरीब, किसान, मजदूर, महिला एवं युवा का सशक्तिकरण करेगा। इसे वास्तविक अर्थों में 'आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था' वाला बजट कहा जा सकता है जो पूरे देश के आत्मविश्वास और उज्ज्वल भविष्य को दर्शाता है।

आज जबकि वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वे के आंकड़े 9.2 प्रतिशत विकास दर दिखा रहे हैं, भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे ऊंची विकास दर वाला देश बन गया है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कोविड-19 महामारी की चुनौतियों को अवसर में परिवर्तित करते हुए प्राप्त की गई है। यह सब समय पर उचित निर्णयों, दूरदर्शी नीतियों, सर्वसमावेशी पहलों एवं दृढ़ राजनैतिक इच्छा के कारण संभव हुआ है। बजट न केवल उन नीतियों का समावेशन करता है, बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था, फिनटेक, तकनीक आधारित विकास, ऊर्जा पारेषण एवं जलवायु परिवर्तन संबंधित पहलों पर विशेष बल देता है। रोजगार वृद्धि के संकल्प को 14 क्षेत्रों में पीएलआई बढ़ाने के निर्णय में देखा जा सकता है जिससे 30 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त उत्पादन का मार्ग प्रशस्त तो होगा ही, साथ ही 60 लाख नए रोजगार भी सृजित होंगे।

आज जबकि वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वे के आंकड़े 9.2 प्रतिशत विकास दर दिखा रहे हैं, भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे ऊंची विकास दर वाला देश बन गया है

आज जबकि पूरा विश्व कोविड-19 महामारी के झंझावातों से गुजर रहा है, बजट 2022-23 को बढ़ाकर न केवल 39.45 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, बल्कि वित्तीय घाटा भी 6.9 प्रतिशत से घटाकर 6.4 प्रतिशत किया गया है। वर्तमान परिस्थितियों में यह अत्यंत प्रशंसनीय प्रयास है। साथ ही पूंजीगत व्यय में 35.4 प्रतिशत की भारी वृद्धि से 7.5 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश से भारी-भरकम निजी निवेश भी अर्थव्यवस्था में होगा। प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के सात इंजन- रोड, रेलवे, हवाई अड्डा, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग एवं सहायक अवसंरचना पर दिए गए विशेष बल से पूरी अर्थव्यवस्था का कायाकल्प होगा। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए भारी आवंटन, कृषि एवं ग्रामीण उद्यमों के स्टार्ट-अप के लिए भारी राशि, कृषि उपज के आकलन, भूमि के पट्टों के डिजिटलीकरण तथा कीटनाशक एवं पोषण तत्वों के छिड़काव के लिए 'किसान ड्रोन' के प्रावधानों से कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे। केन एवं बेतवा नदियों को जोड़ने वाली परियोजना से पूरे बुंदेलखंड में खुशहाली आएगी। लघु, मध्यम एवं छोटे उद्यमों, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के साथ-साथ 'सक्षम आंगनवाड़ी,' 'हर घर, नल से जल' सबके लिए आवास, वाइब्रेंट ग्राम कार्यक्रम जैसे प्रावधानों से बजट का स्वरूप सर्वसमावेशी एवं सर्वव्यापी बन गया है।

बजट 2022-23 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले से दिए गए आह्वान के पूरी तरह अनुरूप है। स्वतंत्रता के 'अमृत महोत्सव' पर उन्होंने कहा था कि आने वाला 25 वर्ष देश के लिए 'अमृत काल' है। यह 'अमृत काल' देश को स्वतंत्रता के 100 वर्ष की ओर ले जाएगा। इस अमृतकाल का उपयोग प्रभावी ढंग से करते हुए उन्होंने राष्ट्र से 'आत्मनिर्भर भारत' का संकल्प लेने का आह्वान किया था। बजट 2022-23 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दृष्टि एवं दिशा के अनुरूप न केवल व्यापक अवसंरचना निर्माण पर बल देता है, बल्कि हर क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' प्राप्त करने के लिए कृतसंकल्पित है। यहां तक कि पूर्व कांग्रेसी सरकारों द्वारा दशकों से उपेक्षित रक्षा क्षेत्र में भी नए उद्योगों, स्टार्ट-अप्स, शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकता के 68 प्रतिशत साजो-सामान देश के अंदर से ही क्रय करने का प्रावधान किया गया है। लगभग हर क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' को बढ़ाने पर बल दिया गया है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को 'अमृतकाल' में 'आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था' का बजट 2022-23 के माध्यम से एक नए युग का सूत्रपात करने के लिए बहुत-बहुत बधाई। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

केन्द्रीय बजट 2022-23

नए भारत का 'आत्मनिर्भर बजट'

केन्द्रीय बजट 2022-23 शक्तिशाली नए भारत का 'आत्मनिर्भर बजट' है। यह विकासोन्मुख, रोजगारपरक, अर्थव्यवस्था को गति देने वाला, वित्तीय समावेशन व वित्तीय स्थिरता प्रदान करने वाला तथा गरीब-किसान-मजदूर-युवा व महिलाओं को सशक्त करने वाला बजट है। बजट में लोगों को आवास, बिजली, रसोई गैस तथा हर घर जल सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को संसद में केन्द्रीय बजट 2022-23 प्रस्तुत करते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो दुनिया की समस्त बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है। कोविड महामारी के प्रतिकूल प्रभावों से उभरकर देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह से समग्र रूप से बड़ी तेजी के साथ रिकवर कर रही है, वह हमारे देश की दमदार मजबूती को दर्शाती है।

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत 'आजादी का अमृत महोत्सव' मना रहा है और इसके साथ ही हमारा देश अब 'अमृत काल' में प्रवेश कर गया है जो भारत@100 तक पहुंचने में 25 वर्षों की लंबी अवधि को दर्शाता है। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उल्लेख किए गए विजन को साकार करने का लक्ष्य रखा है और ये निम्नलिखित हैं:

- वृहद-अर्थव्यवस्था स्तर के विकास पर फोकस करने के साथ-साथ सूक्ष्म-अर्थव्यवस्था स्तर के समावेशी कल्याण पर फोकस करना
- डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं फिनटेक, प्रौद्योगिकी आधारित विकास, ऊर्जा संबंधी बदलाव और जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देना, और
- निजी निवेश से शुरू होने वाले लाभप्रद आर्थिक चक्र पर भरोसा करना और इसके साथ ही सार्वजनिक पूंजीगत निवेश के बल पर निजी निवेश जुटाने में मदद मिलना

वर्ष 2014 से ही सरकार देश के नागरिकों, विशेषकर गरीबों एवं हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने पर अपना ध्यान केन्द्रित करती रही है और इसके साथ ही लोगों को आवास, बिजली, रसोई गैस मुहैया कराने तथा जल तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। यही नहीं, सरकार ने वित्तीय समावेश एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सुनिश्चित करने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं और इसके साथ ही सरकार ने समस्त अवसरों का उपयोग करने में गरीबों की क्षमता बढ़ाने के लिए अपनी ठोस प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

वित्त मंत्री ने बताया कि 'आत्मनिर्भर भारत' विजन को साकार करने के लिए 14 सेक्टरों में दिए जा रहे उत्पादकता आधारित प्रोत्साहन पर व्यापक अनुकूल प्रतिक्रिया हुई है जिनमें 60 लाख नए रोजगारों को सृजित करने के साथ-साथ अगले पांच वर्षों के दौरान 30 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त उत्पादन करने की क्षमता है। नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति के कार्यान्वयन के मुद्दे पर विस्तार से बताते हुए श्रीमती सीतारमण ने

कहा कि एयर इंडिया के स्वामित्व के रणनीतिक हस्तांतरण का कार्य पूरा हो गया है, एनआईएनएल (नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड) के रणनीतिक साझेदार का चयन हो चुका है, एलआईसी का सार्वजनिक निर्गम जल्द ही आने की आशा है और अन्य संबंधित प्रस्ताव भी वर्ष 2022-23 के लिए प्रक्रियाधीन हैं।

पीएम गतिशक्ति

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बजट विकास को निरंतर नई गति दे रहा है इसमें इस समानांतर पथ का उल्लेख किया गया हैः (1) अमृत काल के लिए ब्लू प्रिंट, जो अत्याधुनिक एवं समावेशी है और जिससे हमारे युवा, महिलाएं, किसान, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सीधे तौर पर लाभान्वित होंगी, और (2) अत्याधुनिक अवसंरचना के लिए व्यापक सार्वजनिक निवेश, भारत@100 के लिए तैयार होना और इसका मार्गदर्शन 'पीएम गतिशक्ति' द्वारा किया जाएगा और यह बहु-विध दृष्टिकोण में सामंजस्य से लाभान्वित होगा। इस समानांतर पथ पर आगे बढ़ते हुए वित्त मंत्री ने निम्नलिखित चार प्राथमिकताओं को रेखांकित कियाः

- पीएम गतिशक्ति
- समावेशी विकास
- उत्पादकता बढ़ाना एवं निवेश, उभरते अवसर, ऊर्जा के स्वरूप में बदलाव और जलवायु कार्रवाई
- निवेश का वित्तपोषण करना

साथ ही, श्रीमती सीतारमण ने यह भी कहा कि वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा और सार्वजनिक संसाधनों के पूरक के तौर पर वित्तपोषण के अभिनव तरीकों के जरिए 20,000 करोड़ रुपये जुटाये जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीपीपी मोड के जरिए चार स्थानों पर मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने के लिए वर्ष 2022-23 में ठेके दिए जाएंगे।

रेलवे

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि रेलवे में 'एक स्टेशन-एक उत्पाद' अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा, ताकि स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को आवश्यक मदद मिले सके। इसके अलावा, 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत वर्ष 2022-23 में 2,000 किलोमीटर लंबे नेटवर्क को 'कवच' के अंतर्गत लाया जाएगा जो सुरक्षा और क्षमता वर्धन के लिए स्वेदशी विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी है। उन्होंने यह भी बताया कि अगले तीन वर्षों में बेहतर ऊर्जा दक्षता और यात्रियों को बेहतरीन यात्रा अनुभव दिलाने वाली नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी और इसके साथ ही मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे।

कृषि

वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा जिसके तहत प्रथम चरण में गंगा नदी के किनारे पांच किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर में स्थित किसानों की भूमि पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। फसल आकलन, भूमि रिकॉर्डों के डिजिटलीकरण और कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए 'किसान ड्रोन' के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि तिलहन आयात पर निर्भरता कम करने के लिए एक तर्कसंगत एवं व्यापक योजना लागू की जाएगी, ताकि देश में तिलहन का उत्पादन बढ़ाया जा सके।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली केन-बेतवा संपर्क परियोजना को कार्यान्वित किया जाएगा जिसका उद्देश्य किसानों के

यह बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच विकास का नया विश्वास लेकर आया है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक फरवरी को कहा कि यह बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच विकास का नया विश्वास लेकर आया है। श्री मोदी ने कहा कि ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा।

लोकसभा में केंद्रीय बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद अपनी टिप्पणी में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट मोर इन्फ्रास्ट्रक्चर, मोर इनवेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रीन जॉब्स का भी क्षेत्र और खुलेगा। श्री मोदी ने कहा कि यह बजट न केवल समसामयिक समस्याओं का समाधान करता है, बल्कि युवाओं के उज्ज्वल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है।

उन्होंने कहा कि किसानों के लिए ड्रोन, वंदे भारत रेलगाड़ियां, डिजिटल मुद्रा, 5-जी सेवाएं, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ईकोसिस्टम जैसे कदमों के माध्यम से जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिकता और प्रौद्योगिकी की खोज से हमारे युवाओं, मध्यम वर्ग, गरीबों, दलित और पिछड़ा वर्ग को अत्यधिक लाभ होगा।

श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है— गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो; इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है।

प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट; ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी।

श्री मोदी ने कहा कि भारत के कोटि-कोटि जनों की आस्था, मां गंगा की सफाई के साथ-साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल; इन पांच राज्यों में गंगा किनारे नैचुरल फॉर्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे गंगा को रसायन मुक्त बनाने में भी मदद मिलेगी।

श्री मोदी ने कहा कि बजट के प्रावधानों का उद्देश्य कृषि को आकर्षक और नए अवसरों से परिपूर्ण बनाना है। नए कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कोष और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए पैकेज जैसे उपायों से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी खरीद के जरिए 2.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं।

श्री मोदी ने कहा कि इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई अन्य योजनाओं का ऐलान किया गया है। डिफेंस के कैपिटल बजट का 68 परसेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ भारत के एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा। उन्होंने कहा कि 7.5 लाख करोड़ रुपये का सार्वजनिक निवेश अर्थव्यवस्था को नई शक्ति प्रदान करेगा और छोटे और अन्य उद्योगों के लिए नए अवसर पैदा करेगा।

प्रधानमंत्री ने अंत में कहा कि मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस पीपुल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बजट के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं। ■

यह गरीबों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 1 फरवरी, 2022 को 'बजट 2022-23' पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण एवं उनकी पूरी टीम को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव काल का आम बजट 2022-23 गरीब-कल्याण बजट है। यह गरीबों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। यह ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों के विकास को समर्पित बजट है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर की अवधारणा को चरितार्थ करने वाला बजट है। यह ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है।

श्री नड्डा के वक्तव्य के प्रमुख बिंदु

- बजट का आकार बढ़ाकर 39.45 लाख करोड़ करना, कोरोनाकाल में भी भारत की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। राजकोषीय घाटा (Fiscal deficit) का लक्ष्य 6.9 प्रतिशत से घटाकर 6.4 प्रतिशत करना बहुत बड़ी उपलब्धि है।
- श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के साए में पेश किया गया दूसरा बजट है। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक एक नया आयाम देते हुए यह बजट सभी वर्गों और छोटे-बड़े उद्यमियों की आशाओं-आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। यह महज एक साल के डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, बल्कि देश के लिए अगले 25 साल की बुनियाद रखने वाला ब्लू प्रिंट है।
- पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 100 लाख करोड़ रुपये की गतिशक्ति योजना लॉन्च की थी। इस बजट में गतिशक्ति को एक नई उड़ान मिली है।
- इस बजट में 'आत्मनिर्भर भारत'के लक्ष्यों को पाने के लिए शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना को जबरदस्त रेस्पांस मिला है। इससे लगभग 60 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी और अगले 5 सालों में 30 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त उत्पादन होगा। ये नए भारत की नींव रखेगा।
- 25 हजार किलोमीटर के नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा, जिस पर 20,000 करोड़ रुपये का खर्च करने का प्रावधान किया गया है। देश में 5 बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए जल संसाधन विकास मंत्रालय की भी मदद से कार्य करने की योजना बनाई गई है। बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए बजट में 44,605 करोड़ रुपये खर्च किये जाने का प्रावधान किया गया है जिसके तहत पानी की समस्या से जूझ रहे बुंदेलखंड क्षेत्र के लगभग 62 लाख लोगों को पेय जल मिलेगा।
- सरकार ने एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी का प्रावधान बजट में किया है। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठाये गए हैं। गंगा किनारे रहने वाले किसानों की जमीन पर खास फोकस दिया जाएगा, जिसके लिए 5 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई गई है। लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन की योजना पर भी जोर दिया गया है।
- इस बजट में 130 लाख एमएसएमई की मदद के लिए सरकार द्वारा अतिरिक्त कर्ज़ मुहैया कराने के लिए कदम उठाये गए हैं। अगले 5 साल में एमएसएमई को लगभग 6,000 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही 2 लाख करोड़ के अतिरिक्त ऋण की भी व्यवस्था की गयी है।
- इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना को और विस्तार दिया गया है। गरीबों के लिए 80 लाख अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। इसके लिए बजट में 48,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।
- भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करते हुए श्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने 2022-23 में राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन करने की घोषणा की है।
- नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान है।
- देश के सभी 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को बैंकिग से जोड़ा जा चुका है।
- महामारी के दौरान स्कूल बंद रहने से गांव के बच्चों को दो साल शिक्षा से वंचित रहना पड़ा। पीएम ई-विद्या के तहत ऐसे बच्चों के लिए एक क्लास— एक टीवी चैनल प्रोग्राम के तहत अब चैनल 12 से बढ़ाकर 200 कर दिए जाएंगे। ये चैनल क्षेत्रीय भाषाओं में होंगे। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी।
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25 प्रतिशत रक्षा अनुसंधान एवं विकास उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए खोला जाएगा। ■

बजट 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहन देगा: राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को एक बेहतरीन केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि बजट 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहन देगा, मांग को बढ़ावा देगा और एक मजबूत, समृद्ध एवं आत्मविश्वास से भरे भारत के लिए क्षमता का निर्माण करेगा।

रक्षा मंत्री ने एक फरवरी को सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि बजट 'आत्मनिर्भरता' और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकास तथा जन-हितैषी सुधारों पर सरकार के फोकस को रेखांकित करता है। उन्होंने इसे विकासोन्मुखी बजट कहा, जिसमें न्यू इंडिया की ऊर्जा का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25 प्रतिशत स्टार्टअप और निजी संस्थाओं के लिए आरक्षित करने के प्रस्ताव को एक उत्कृष्ट कदम बताया।

रक्षा मंत्री ने इस तथ्य की सराहना करते हुए कहा कि इस वर्ष के बजट में प्रभावी पूंजीगत व्यय के लिए कुल परिव्यय को 35.4 प्रतिशत बढ़ाकर 10.6 लाख करोड़ से अधिक कर दिया है, जिसमें से अधिकांश धन का उपयोग देश में सामाजिक और अवसंरचना विकास के लिए किया जायेगा।

घरेलू खरीद के लिए रक्षा खरीद बजट के 68 प्रतिशत आवंटन पर श्री सिंह ने कहा कि यह 'वोकल फॉर लोकल' के अनुरूप है और निश्चित रूप से घरेलू रक्षा उद्योगों को बढ़ावा देगा।

भारत को 'आत्मनिर्भर' बनायेगा यह बजट: अमित शाह

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आम बजट को दूरगामी बताते हुए कहा कि यह बजट भारतीय अर्थव्यवस्था में आमूल परिवर्तन लाने वाला साबित होगा। श्रृंखलाबद्ध ट्वीटों में श्री शाह ने एक फरवरी को कहा कि मोदी सरकार का यह बजट भारत को 'आत्मनिर्भर' बनायेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिये मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को बधाई देता हूं।

गृह और सहकारिता मंत्री ने कहा कि बजट का आकार बढ़ाकर 39.45 लाख करोड़ रुपये करना, कोविड-19 महामारी के दौरान भी भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 6.9 प्रतिशत से घटाकर 6.4 प्रतिशत करना बहुत बड़ी उपलब्धि है।

श्री शाह ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी ने सहकारिता क्षेत्र में एएमटी (वैकल्पिक न्यूनतम कर) दर को 18.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत और सरचार्ज को 12 प्रतिशत से सात प्रतिशत घटाकर दशकों तक सहकारिता क्षेत्र के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करके उसे बाकी क्षेत्रों के बराबर लाने का काम किया है। यह श्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प को सिद्ध करने में सहायक होगा।

उन्होंने कहा कि पूंजीगत निवेश को 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपये करने के लिये मैं श्री नरेन्द्र मोदी का अभिनन्दन करता हूं।

9.08 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधाएं, 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति, 103 मेगावाट पनबिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना है। इस परियोजना के लिए संशोधित बजट अनुमान 2021-22 में 4,300 करोड़ रुपये और वर्ष 2022-23 में 1,400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

इसके अलावा, पांच नदी संपर्कों यथा दमनगंगा-पिनजाल, पार-तापी-नर्मदा, गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार और पेन्नार-कावेरी की मसौदा डीपीआर को अंतिम रूप दे दिया गया है और लाभार्थी राज्यों के बीच आम सहमति होने के साथ ही केन्द्र सरकार इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सहायता दे देगी।

एमएसएमई

वित्त मंत्री ने यह बात रेखांकित की कि आपातकालीन ऋण लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत 130 लाख से भी अधिक एमएसएमई को अत्यंत आवश्यक अतिरिक्त ऋण मुहैया कराया गया है, जिससे उन्हें महामारी के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी। हालांकि, उन्होंने कहा कि विशेषकर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा मुहैया कराए जाने वाली आतिथ्य एवं संबंधित सेवाओं का कुल कारोबार अभी तक अपने महामारी-पूर्व स्तर पर नहीं पहुंच पाया है। इन पहलुओं पर विचार करने के बाद ईसीएलजीएस की अवधि मार्च, 2023 तक बढ़ा दी जाएगी।

श्रीमती सीतारमण ने बताया कि इसके गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये बढ़ाकर कुल मिलाकर 5 लाख करोड़ रुपये कर दिया जाएगा। इसके तहत अतिरिक्त राशि को विशेषकर आतिथ्य एवं संबंधित उद्यमों के लिए निर्दिष्ट किया जा रहा है।

कौशल विकास एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

'कौशल विकास एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा' विषय के बारे में विस्तार से बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि विभिन्न अनुप्रयोगों के जरिए 'ड्रोन शक्ति' को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ 'एक सेवा के रूप में ड्रोन (डीआरएएएस)' के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी राज्यों में स्थित चुनिंदा आईटीआई में कौशल बढ़ाने के लिए आवश्यक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में आवश्यक चिंतन-मनन को बढ़ावा देने वाले आवश्यक कौशल को प्रोत्साहन देने, रचनात्मकता की गुंजाइश के लिए विज्ञान एवं गणित में 750 वर्चुअल प्रयोगशालाएं और उन्नत शिक्षण माहौल के लिए 75 कौशल ई-लैब वर्ष 2022-23 में स्थापित की जाएंगी।

देशभर के विद्यार्थियों को उनके द्वार पर व्यक्तिगत तौर पर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विश्वस्तरीय गुणवत्तापूर्ण सर्वसुलभ शिक्षा देने के लिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यह विभिन्न भारतीय भाषाओं और आईसीटी फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जाएगा। यह विश्वविद्यालय नेटवर्क आधारित हब-स्पोक मॉडल पर बनाया जाएगा, जिसमें हब भवन अत्याधुनिक आईसीटी विशेषज्ञता से युक्त होंगे। देश के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक विश्वविद्यालय और संस्थान हब-स्पोक के नेटवर्क के रूप में सहयोग करेंगे।

स्वास्थ्य

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 'नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम' के लिए एक ओपन प्लेटफार्म चालू किया जाएगा। इसमें चिकित्साकर्मी एवं स्वास्थ्य सुविधाओं, अद्वितीय स्वास्थ्य पहचान, कंसेंट फ्रेमवर्क और सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता को डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घोषणा करते हुए कहा कि हर घर, नल से जल के लिए 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। इस समय 8.7 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया है और इसमें से 5.5 करोड़ परिवारों को पिछले 2 वर्षों में नल का पानी उपलब्ध करा दिया गया है।

इसी प्रकार वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी, दोनों ही क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के चिन्हित एवं पात्र लाभार्थियों के लिए 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। इसके लिए 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

उत्तर-पूर्व प्रधानमंत्री विकास पहल

उत्तर-पूर्व परिषद् के माध्यम से 'उत्तर-पूर्व प्रधानमंत्री विकास पहल' नामक एक नई योजना चलाई जाएगी। इससे पीएम गतिशक्ति की भावना के अनुरूप उत्तर-पूर्व की जरूरतों के मुताबिक बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक विकास की परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण किया जा सकेगा। इसके लिए 1,500 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आवंटन किया जा रहा है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में कमियों की भरपाई करते हुए युवाओं एवं महिलाओं के लिए आजीविका से जुड़ी गतिविधियों चलाई जाएंगी।

वित्तीय समावेशन (1.5 लाख डाक घरों में कोर बैंकिंग सिस्टम)

2022 में शत-प्रतिशत 1.5 लाख डाक घरों में कोर बैंकिंग सिस्टम चालू हो जाएगा, जिससे 'वित्तीय समावेशन' संभव होगा और 11 नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से अपना खाता देखा जा सकेगा और डाक घर के खाते से बैंक खाते के बीच धन का ऑनलाइन अंतरण भी हो सकेगा। इससे विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'इंटर-ऑपरेबिलिटी और वित्तीय समावेशन' की सुविधा उपलब्ध होगी।

देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मनाने के लिए सरकार ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिटों की स्थापना का प्रस्ताव किया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता तक अनुकूल तरीके से देश के सभी हिस्सों में डिजिटल बैंकिंग की पहुंच कायम हो।

5जी प्रौद्योगिकी

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि सामान्य रूप से दूर संचार और विशेष रूप से 5जी प्रौद्योगिकी, प्रगति और रोजगार के अवसर प्रदान करने में समर्थ बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपेक्षित स्पैक्ट्रम नीलामियों को निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा 2022-23 के भीतर 5जी मोबाइल सेवाओं के आरंभ को आसान बनाने के लिए 2022 में निष्पादित किया जाएगा।

रक्षा

रक्षा के मोर्चे पर हमारी सरकार निर्यातों को कम करने और सशस्त्र बलों के लिए उपकरणों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। पूंजीगत खरीद बजट के 2021-22 में 58 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए 68 प्रतिशत तक धनराशि का प्रावधान किया जाएगा। रक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के कार्यों को रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट के 25 प्रतिशत हिस्से को उद्योग, स्टार्ट-अप और शिक्षा जगत के लिए खोल दिया जाएगा।

पूंजीगत व्यय में 35.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी (2022-23 में 7.5 लाख करोड़ रुपये का व्यय)

वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि सार्वजनिक निवेश को आगे बने रहने की जरूरत है और 2022-23 में निजी निवेश और मांग को बढ़ाना भी जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए एक बार फिर केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय में तेजी से बढ़ोतरी की गई है। अभी यह चालू वर्ष में 5.54 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें 35.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी करके 2022-23 में 7.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह 2019-20 के व्यय से 2.2 गुना से भी अधिक बढ़ गया है और 2022-23 में यह परिव्यय जीडीपी का 2.9 प्रतिशत होगा। इस निवेश के साथ केंद्र सरकार का 'कारगर पूंजीगत व्यय' 2022-23 में अनुमानतः 10.68 लाख करोड़ रुपये का हो जाएगा, जो कि जीडीपी का लगभग 4.1 प्रतिशत होगा।

सहकारी संघवाद (राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन)

सहकारी संघवाद की सच्ची भावना को जाहिर करते हुए केंद्र सरकार ने 'राज्यों को वित्तीय सहायता के लिए पूंजी निवेश योजना' के परिव्यय को 10,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर चालू वर्ष के संशोधित अनुमान में 15,000 करोड़ रुपये कर दिया है। इसके अलावा 2022-23 के लिए अर्थव्यवस्था में सभी निवेशों को प्रेरित करने के उद्देश्य से राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। ये 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण राज्यों को दिए जाने वाले सामान्य कर्ज के अलावा हैं। इस प्रकार के आवंटन का इस्तेमाल पीएम गतिशक्ति से जुड़े निवेशों और राज्यों की अन्य उत्पादक पूंजी निवेश में किया जाएगा।

राजकोषीय घाटे में कमी

अपने बजट भाषण के भाग ए को समाप्त करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि चालू वर्ष में संशोधित वित्तीय घाटा जीडीपी का अनुमानतः 6.9 प्रतिशत है, जबकि बजट अनुमान में यह 6.8 प्रतिशत है। 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का अनुमानतः 6.4 प्रतिशत है, जो कि राजकोषीय मजबूती के उस मार्ग के अनुरूप भी है। जिसकी पिछले वर्ष घोषणा की गई थी कि 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत से निचले स्तर पर लाया जाएगा। 2022-23 के राजकोषीय घाटे के स्तर को निर्धारित करते समय उन्होंने मजबूती और टिकाऊपन के लिए सार्वजनिक निवेश के माध्यम से प्रगति के पोषण का आह्वान किया।

प्रत्यक्ष कर

प्रत्यक्ष कर के बारे में यह बजट करदाताओं को त्रुटियों में सुधार के लिए दो वर्ष के भीतर अपडेट की हुई आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देता है। यह दिव्यांगजनों के लिए भी कर राहत प्रदान करता है। यह बजट सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर दर और अधिभार में भी कमी लाने का प्रस्ताव करता है। स्टार्ट-अप के लिए प्रोत्साहन के तौर पर पात्र स्टार्ट-अप की शुरुआत की अवधि को एक अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।

बजट में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच समानता लाने के उद्देश्य से एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर की कटौती की सीमा को बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया गया है। नई विनिर्माण इकाइयों को भी रियायती कर प्रणाली के तहत प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्चुअल संसाधनों के अंतरण से प्राप्त आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया जाएगा।

अप्रत्यक्ष कर

अप्रत्यक्ष कर के मामले में केन्द्रीय बजट के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रों में सीमा-शुल्क प्रशासन को पूरी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी से सक्षम बनाया जाएगा। यह पूंजीगत वस्तुओं एवं परियोजनागत आयातों में रियायती दरों को क्रमिक रूप से हटाने और 7.5 प्रतिशत का साधारण प्रशुल्क प्रदान करता है। बजट में सीमा-शुल्क छूट और प्रशुल्क सरलीकरण की समीक्षा का उल्लेख किया गया है और इसमें 350 से अधिक छूट प्रविष्टियों को धीरे-धीरे हटाए जाने का प्रस्ताव है। ■

इस बजट का फोकस गरीब, मिडिल क्लास और युवाओं को बुनियादी सुविधाएं देने और आय के स्थायी समाधानों से जोड़ने पर है: नरेन्द्र मोदी

वर्चुअल संवाद कार्यक्रम 'आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 फरवरी, 2022 को केंद्रीय बजट 2022-23 के परिप्रेक्ष्य में देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित वर्चुअल संवाद कार्यक्रम 'आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था' को संबोधित किया और इस बार के बजट के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही, इस प्रो-पीपल और प्रोग्रेसिव बजट के विभिन्न आयामों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री बी.एल. संतोष, पार्टी के सभी राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, केंद्र सरकार में मंत्री तथा पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं नेता डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली और कई अन्य जगहों से वर्चुअली जुड़े। देश भर में लगभग 1800 स्थानों से राज्य, जिला और मंडल स्तर से भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री, राज्य सरकार में मंत्री, पार्टी पदाधिकारी, पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं लाखों पार्टी कार्यकर्ता जुड़े।

श्री मोदी ने कहा कि बीते सात वर्षों में जो निर्णय लिए गए, जो नीतियां बनीं, पहले की जिन नीतियों में सुधार हुआ, उस वजह से आज भारत की अर्थव्यवस्था का निरंतर विस्तार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब गरीब को मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं तो वो अपनी ऊर्जा, अपने विकास, देश के विकास में लगाता है। इस बजट का भी फोकस गरीब, मिडिल क्लास और युवाओं को बुनियादी सुविधाएं देने और आय के स्थाई समाधानों से जोड़ने पर है।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के प्रयासों से आज देश में करीब-करीब 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचने लगा है। बजट में घोषणा की गई है कि इस साल करीब 4 करोड़ ग्रामीण घरों को पाइप से पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। इस पर 60 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे।

श्री मोदी ने कहा कि देश की कृषि को टेक्नॉलॉजी आधारित और कैमिकल फ्री बनाने के लिए बड़े कदम इस बजट में उठाए गए हैं। बीते बजट में हमने किसान रेल और किसान उड़ान की सुविधा सुनिश्चित की, अब किसान ड्रोन किसान का नया साथी बनने वाला है। उन्होंने कहा कि भाजपा युवा आकांक्षाओं और युवा सपनों को समझती है। इस बजट में स्टार्ट अप्स के लिए टैक्स बेनिफिट को आगे बढ़ाया गया है।

उन्होंने कहा कि आज के अखबारों में डिजिटल करेंसी की भी काफी चर्चा है। इससे डिजिटल इकॉनॉमी को बहुत बल मिलेगा। ये डिजिटल रुपया अभी जो हमारी फिजिकल करेंसी है उसका ही डिजिटल स्वरूप होगा और इसे आरबीआई द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। इसको फिजिकल करेंसी से एक्सचेंज किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि इस बार बजट में एक बात जो सबसे खास, और सबसे अलग है तो वो है — पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये कितना बड़ा कदम है और इसका असर कितना बड़ा होगा, इस बात का अनुमान इससे लगा सकते हैं कि वर्ष 2013-14 में सार्वजानिक निवेश सिर्फ 1 लाख 87 हजार करोड़ था। इस बजट में ये 7 लाख 50 हजार करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि 2014 में देश में 90 हजार किलोमीटर नेशनल हाइवेज थे। ये 90 हजार किलोमीटर हाइवे पिछले 70 सालों में बने थे। हमने पिछले 7 सालों में ही 50 हजार किलोमीटर नेशनल हाइवेज बनाए हैं। पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान के तहत देश में नए हाइवे और बनाएंगे। ■

यह बजट आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जमीन पर उतारने वाला है : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने आम बजट 2022-23 के परिप्रेक्ष्य में आयोजित 'आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था' वर्चुअल कार्यक्रम में देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत और अभिनंदन किया।

श्री नड्डा ने कहा कि आजादी के 'अमृत काल' में देश के लिए अगले 25 साल की बुनियाद रखनेवाले 'आत्मनिर्भर भारत' की नींव रखने का प्रधानमंत्रीजी का जो संकल्प है, इस बार का बजट उस संकल्प को जमीन पर उतारने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्रीजी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा कल संसद में पेश किया गया आम बजट प्रधानमंत्रीजी की सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबके प्रयास' की नीति को चरितार्थ कर रहा है।

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख नए रोजगार का सृजन होगा

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को संसद में केन्द्रीय बजट 2022-23 पेश किया। इस बजट में सर्व कल्याण के साथ-साथ व्यापक अवसंरचना के विकास पर काफी जोर दिया गया है। बजट में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत अनुमानित है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है

केंद्रीय बजट 2022-23 की मुख्य बातें:

- भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत अनुमानित है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है।
- 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख नए रोजगार का सृजन होगा।
- पीएलआई योजना में 30 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है।

अगले 25 साल भारत@100 के अमृत काल में प्रवेश करते हुए बजट में 4 प्राथमिकताओं में विकास पर जोर दिया गया है:

- पीएम गतिशक्ति
- समेकित विकास
- उत्पाद संवर्धन एवं निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य
- निवेश को वित्तीय मदद

पीएम गतिशक्ति

- पीएम गतिशक्ति को बढ़ावा देने वाले 7 कारक—सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना हैं।
- पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान के दायरे में आर्थिक बदलाव के सभी 7 कारक निर्बाध बहुपक्षीय कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक के दायरे में आ जाएंगे।
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में इन 7 कारकों से जुड़ी परियोजनाओं को पीएम गतिशक्ति फ्रेमवर्क से जोड़ दिया जाएगा।

सड़क परिवहन, रेल मार्ग (400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण)

- राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 2022-23 में 25000 किलोमीटर का विस्तार दिया जाएगा।
- स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की संकल्पना।
- 2022-23 में देसी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि कवच के तहत रेल मार्ग नेटवर्क में 2000 किलोमीटर जोड़ा जाएगा।
- अगले 3 साल के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा।

कृषि

- गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान।
- देशभर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। शुरू में गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर की चौड़ाई तक के गलियारे वाले किसानों की जमीनों पर ध्यान दिया जाएगा।
- केन-बेतवा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 1400 करोड़ रुपए का परिव्यय। केन-बेतवा लिंक परियोजना से किसानों की 9.08 लाख हेक्टेयर जमीनों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी।

एमएसएमई

- उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा।
- 130 लाख एमएसएमई को इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत अतिरिक्त कर्ज दिया गया।
- ईसीएलजीएस को मार्च, 2023 तक बढ़ाया जाएगा। ईसीएलजीएस के तहत गारंटी कवर को 50000 करोड़ रुपए बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ कर दिया जाएगा।

कौशल विकास

- ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिए नागरिकों की कुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवलीहुड (डीईएसएच-स्टैक ई-पोर्टल) लॉन्च किया जाएगा।
- पीएम ई-विद्या के एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा।
- व्यक्तिगत तौर पर पढ़ाई करने के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

स्वास्थ्य; हर घर, नल से जल; सभी के लिए आवास

- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के लिए खुला मंच शुरू किया जाएगा।
- गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखरेख सेवाओं के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

- हर घर, नल से जल के तहत वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल

- पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे एवं सामाजिक विकास परियोजनाओं और वित्त पोषण के लिए नई योजना पीएम-डीईवीआईएनई शुरू की गई।
- इस योजना के तहत युवा और महिलाओं को आजीविका गतिविधियों में समर्थ बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपये का शुरुआती आवंटन।
- शत-प्रतिशत 1.5 लाख डाकघरों को मुख्य बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया जाएगा।
- इम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी वाले ई-पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे।

रक्षा में आत्मनिर्भरता, दूरसंचार क्षेत्र

- 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित पूंजीगत खरीदारी बजट का 68 प्रतिशत निर्धारित किया गया, जो 2021 में 58 प्रतिशत के मुकाबले अधिक है।
- 25 प्रतिशत रक्षा अनुसंधान विकास बजट के साथ उद्योग स्टार्टअप्स और शिक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान विकास खोला जाएगा।
- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के एक हिस्से के रूप में 5जी के लिए एक मजबूत इको-सिस्टम स्थापित करने के लिए डिजाइन जनहित विनिर्माण के लिए योजना।
- आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, भू-स्थानिक प्रणालियों और ड्रोनों, सेमीकंडक्टर और इसके इको-सिस्टम अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जीनोमिक्स और फार्मास्युटिकल्स हरित ऊर्जा और स्वच्छ गतिशीलता प्रणालियों जैसे सनराइज अवसरों में अनुसंधान और विकास के लिए सरकारी योगदान उपलब्ध कराया जाएगा।
- वर्ष 2030 तक स्थापित सौर विद्युत का 280 गीगावॉट लक्ष्य हासिल करने के लिए उच्च दक्षता के सौर मॉड्यूल्स के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 19,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन।

सार्वजनिक पूंजीगत निवेश, डिजिटल रुपया

- 2022-23 में निजी निवेश और मांग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निवेश को जारी रखना।
- वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय 35.4 प्रतिशत तेजी से बढ़कर 7.50 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो मौजूदा वर्ष में 5.54 लाख करोड़ रुपये था।
- वर्ष 2022-23 में परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.9 प्रतिशत रहेगा।
- केन्द्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 2022-23 में 10.68 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो जीडीपी का लगभग 4.1 प्रतिशत है।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2022-23 में डिजिटल रुपये की शुरुआत।
- अर्थव्यवस्था में समग्र प्रोत्साहन के लिए राज्यों को सहायता के लिए वर्ष 2022-23 में एक लाख करोड़ रुपये का आवंटन; 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना, जो सामान्य ऋण के अतिरिक्त है।
- 2022-23 में राज्यों को जीएसडीपी के 4 प्रतिशत का वित्तीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5 प्रतिशत विद्युत क्षेत्र सुधारों में उपयोग किया जाएगा।

राजकोषीय प्रबंधन

- **बजट अनुमान 2021-22:** 34.83 लाख करोड़ रुपये; संशोधित अनुमान 2021-22: 37.70 लाख करोड़ रुपये।
- **वर्ष 2022-23 में कुल अनुमानित व्यय:** 39.45 लाख करोड़ रुपये; वर्ष 2022-23 में उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां: 22.84 लाख करोड़ रुपये।
- चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.9 प्रतिशत (बजट अनुमानों में 6.8 प्रतिशत की तुलना में)।
- वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4 प्रतिशत अनुमानित।

सहकारी समितियां, स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन

- सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर भुगतान को 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया।
- सहकारी समितियों और कंपनियों के लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे।
- राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
- इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के समान सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी।
- कर प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए पात्र स्टार्टअप के निगमन की अवधि को एक साल बढ़ाकर 31.03.2023 तक करने का प्रस्ताव। पहले निगमन की अवधि 31.03.2022 तक वैध।
- किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कर की दर 30 प्रतिशत होगी।
- एसईजेड का सीमा शुल्क प्रशासन पूरी तरह आईटी से संचालित होगा और कस्टम्स नेशनल पोर्टल पर कार्य करेगा, जिसे 30 सितंबर, 2022 से क्रियान्वित किया जाएगा। ■

एक तरफ भाजपा है जिसके पास विजन है, दूसरी तरफ अहंकार से भरे 'नकली समाजवादी' हैं : नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 31 जनवरी, 2022 को 'जन चौपाल' कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश के शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर और गौतम बुद्ध नगर के मतदाताओं के साथ संवाद किया और उनसे जन-जन के विकास के प्रति समर्पित भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार बनाने की अपील की।

उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था में हुए आमूल-चूल परिवर्तन को रेखांकित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोई भूल नहीं सकता कि 5 साल पहले प्रदेश को लेकर क्या चर्चा होती थी? पांच साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे, उन्हीं का कहा शासन का आदेश था। पांच साल पहले व्यापारी लुटते थे, बेटियां घर से बाहर निकलने में घबराती थी और माफिया, सरकारी संरक्षण में खुलेआम घूमते थे। आज यूपी का किसान हों, कर्मचारी हों, व्यापारी हों या फिर माताएं-बहनें-बेटियां, सभी को सुरक्षा और सम्मान मिल रहा है। जो माफिया और गुंडे खुद को कानून से भी बड़ा मानते थे, यूपी की भाजपा सरकार ने उन्हें कानून का मतलब समझा दिया है। पांच साल पहले गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ों के घर-जमीन-दुकान पर अवैध कब्ज़ा का समाचार आये दिन अखबारों की सुर्खियां बनती थीं। हम उत्तर प्रदेश में बदलाव के लिए खुद को खपा रहे हैं, लेकिन वे उत्तर प्रदेश की जनता से यानी आपसे बदला लेने की ठानकर बैठे हैं। इन लोगों ने जिन्हें टिकट दिया है, वह इस बात का एक और सबूत है। बदला लेना ही हमेशा से उनकी सोच रही है। इसलिए मैं देखकर खुश हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता इन दंगाई सोच रखने वालों से बहुत सावधान है, सतर्क है। हमारा काम और उनके कारनामें व कारस्तानी देखकर इस बार भी उत्तर प्रदेश की जनता, भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद देने जा रही है। और इसमें भी जो हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वो खुलकर भाजपा के साथ हैं।

श्री मोदी ने कहा कि शामली, मुज़फ्फरनगर और बागपत शहर में भी कुल मिलाकर 800 घर ही पिछली सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में बनवाए थे। भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इन तीन शहरों में 33 हजार से ज्यादा गरीबों को घर बनवाकर दिए हैं। सहारनपुर शहर में भी पहले वाली सरकार ने सिर्फ 221 घर गरीबों के लिए बनवाए थे। योगी सरकार ने इन्हीं पांच सालों में 18 हजार से ज्यादा घर बनाकर सहारनपुर के गरीबों को दिए हैं। पहले वाली सरकार ने अपने 5 साल में गौतमबुद्ध नगर में केवल 73 घर बनाए थे। यूपी की डबल इंजन की सरकार ने इन्हीं 5 साल में करीब 23 हजार घर बनाकर शहरी गरीबों को दिए हैं। सोचिए, कहां 73 घर और कहां 23 हजार घर। उत्तर प्रदेश की जनता पहले की सरकार में रहने वालों की बदनीयत को अच्छी

तरह जानती है। इन लोगों ने भ्रष्टाचार और रियल एस्टेट माफिया का ऐसा गठबंधन कराया कि एनसीआर के हजारों फ्लैट खरीदारों के जीवन भर की पूंजी लुट गई। इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे मध्यम वर्ग के लोगों को उठाना पड़ा। एक तरफ भाजपा है, जिसके पास विकास का स्पष्ट विजन है, साफ सुथरा ईमानदार और दमदार नेतृत्व है, वहीं दूसरी तरफ अहंकार से भरे, समाज को तोड़ने वाले, किसी भी कीमत पर सत्ता पाने का सपना देख रहे 'नकली समाजवादी' हैं। इन्हें उत्तर प्रदेश की जनता के उत्थान से कोई लेना-देना नहीं है।

मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ एवं नोएडा

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के क्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 4 फरवरी, 2022 को उत्तर प्रदेश के पांच जिलों मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा की जनता को वर्चुअल संबोधित किया और उनसे एक बार पुनः भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार बनाने की अपील की।

श्री मोदी ने कहा कि मुझे याद है, इस साल की शुरुआत में, मेरा पहला दौरा मेरठ का ही हुआ था। उस दिन मौसम खराब था, इसलिए मुझे सड़क मार्ग से आना पड़ा था, लेकिन मेरठ एक्सप्रेसवे की वजह से मैं एक घंटे से भी कम समय में दिल्ली से मेरठ पहुंच गया था।

विपक्ष पर हमला करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये कागज़ी समाजवादी, जो शत प्रतिशत परिवारवादी हैं और इनके सहयोगी इतने सालों तक सत्ता में रहे, लेकिन खेती की समस्या और किसानों की परेशानी को इन्होंने समझा ही नहीं। डबल इंजन की सरकार को खेती और किसान के वर्तमान और भविष्य की चिंता है। इसलिए कृषि का बजट पिछली सरकारों की तुलना में आज छह गुना हो चुका है। पीएम

सम्मान निधि के 70 हज़ार करोड़ रुपए में से बहुत बड़ा हिस्सा यूपी के छोटे किसानों को मिलेगा। एमएसपी खत्म हो जाएगा, ये अफवाह फैलाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन यूपी में डबल इंजन की सरकार ने 2017 से पहले की अपेक्षा एमएसपी पर खरीद में कई गुणा अधिक वृद्धि की है। इस वर्ष भी यूपी सहित देश के किसानों को लाखों करोड़ रुपए एमएसपी के रूप में मिलने वाले हैं।

श्री मोदी ने कहा कि भाजपा डंके की चोट पर कह रही है कि दबंग और दंगाराज यूपी में नहीं अब नहीं लौटेगा। बीते 5 वर्षों में कानून का राज स्थापित करने के लिए पुलिस में लगभग डेढ़ लाख भर्तियां हुई हैं। इससे पहले के 15 सालों में सवा लाख से भी कम भर्तियां हुई थीं।

बिजनौर, मथुरा, आगरा तथा बुलंदशहर

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के क्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 6 फरवरी, 2022 को बिजनौर, मथुरा, आगरा तथा बुलंदशहर के 21 विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की जनता को संबोधित किया और उनसे एक बार पुनः भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार बनाने की अपील की।

श्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने दो टूक कह दिया है कि धन-दौलत, बाहुबल, जातिवाद, संप्रदायवाद के दम पर भले कुछ लोग कितनी ही राजनीति कर लें, लेकिन वो जनता का प्यार नहीं पा सकते। जनता का आशीर्वाद तो उसे ही मिलेगा जो सेवा भावना से सेवक बनकर यूपी के लोगों की सेवा करेगा, यूपी के लोगों का विकास करेगा।

उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों का एक और पसंदीदा खेल होता था। तिजोरियों को भरने का खेल। सब मिलकर खेलते थे। मिलकर खाते थे। आज ऐसे लोगों का पूरा खेल बिगड़ गया है। पहले परिवार ही सरकार थी; अब पूरा यूपी भाजपा सरकार का परिवार है। परिवारवादी सरकारों के लिए सत्ता शासन का माध्यम थी। हमारे लिए सत्ता जनता की सेवा करने का रास्ता है। हम लगातार इसी उद्देश्य से काम कर रहे हैं। हमारी सरकार गांव, गरीब को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।

श्री मोदी ने कहा कि गरीब के घरों को लेकर नकली समाजवादियों का क्या रवैया रहा है, ये मैं आपको जरूर याद दिलाना चाहता हूं। आगरा, मथुरा और बुलंदरशहर के शहरी क्षेत्रों में पिछली सरकार ने आठ हजार से भी कम घर गरीबों के लिए बनवाए थे। पिछले पांच साल में योगी जी की सरकार ने आगरा-मथुरा और बुलंदशहर में ही करीब 85 हजार घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। यूपी की भलाई के लिए इन नकली समाजवादियों और उनके साथियों का सत्ता से दूर रहना आवश्यक है। आज भी वो किसानों से झूठे वादे किए जा रहे हैं, गन्ना किसानों को झूठी बातें बताकर उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी का युवा भूला नहीं है कि कैसे इसी प्रदेश में पहले की सरकारों में नौकरी के लिए क्या योग्यता तय थी? क्या-क्या खेल होते थे? कहां-कहां से खेल होते थे? आज सब लोगों को पर्याप्त और समान अवसर मिल रहें है। यूपी में भाजपा सरकार ने युवाओं को रिकार्ड सरकारी नियुक्तियां दी है। ■

'डबल इंजन की सरकार आने से चीजें कैसे बदलती हैं, इसका बहुत बड़ा उदाहरण ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन है'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 7 फरवरी, 2022 को उत्तराखंड के हरिद्वार और देहरादून के मतदाताओं के साथ वर्चुअल संवाद किया और उनसे उत्तराखंड के विकास के लिए एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत वाली सरकार बनाने की अपील की। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे।

श्री मोदी ने कहा कि मैं सर्वप्रथम देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी को नमन करता हूं। मैं हर उस वीर को नमन करता हूं, जिन्होंने उत्तराखंड की धरती से प्रेरणा लेकर देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीमावर्ती गांवों में प्राथमिकता के आधार पर विकास कर रही है। इस बजट में भी वाइब्रेंट विलेज नाम से एक योजना का ऐलान किया गया है। इस योजना के तहत सीमावर्ती गांवों में संसाधन और सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, ताकि वहां पर्यटन भी बढ़े। डबल इंजन की सरकार आने से चीजें कैसे बदलती हैं, विकास पर लगे हुये ब्रेक कैसे हटते हैं, इसका बहुत बड़ा उदाहरण ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम एक दशक पहले शुरू होना था, लेकिन पिछली ब्रेक वाली सरकार ब्रेक पर ब्रेक लगाती रही। दिल्ली-देहरादून हाइवे का काम भी साल 2000 में शुरू हुआ था लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इसमें रोड़ा अटकाए रखा।

उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए 'पर्वतमाला परियोजना'की घोषणा की है। इससे पहाड़ों पर विकास के नए युग का आरंभ होने जा रहा है। आने वाले समय में यहां पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और युवा अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे।

उत्तराखंड की जनता से अपील करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने उत्तराखंड के विकास के साथ पाप किया है, देश की सुरक्षा के साथ पाप किया है। उत्तराखंड की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। जब आप 14 फरवरी को वोट डालने जाएं तो कांग्रेस को और कांग्रेस के गुनाहों को याद रखें। आप भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाकर राष्ट्र के सम्मान, राष्ट्र के विकास और उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाने का काम करें। ■

विपक्ष भले कितने ही साजिश क्यों न रच ले, भारी बहुमत से योगी आदित्यनाथ सरकार पुनः बनने जा रही है: जगत प्रकाश नड्डा

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के निमित्त भाजपा का सघन चुनाव प्रचार अभियान चल रहा है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने बरेली, इटावा, शिकोहाबाद, हाथरस, कोंच, उरई, माधोगढ़, हापुड़, मुरादाबाद, नोएडा सहित अनेक क्षेत्रों में आयोजित प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रमों को संबोधित कर जनता से एक बार पुनः भारी बहुमत से विकास के प्रति समर्पित प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की योगी आदित्यनाथ सरकार बनाने का आह्वान किया

बरेली

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 28 जनवरी, 2022 को बरेली में आयोजित प्रभावी मतदाता संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीटों पर जीत के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत की सरकार का गठन निश्चित है।

उन्होंने कहा कि चाहे सपा हो, बसपा या कांग्रेस — ये सब एक परिवार की पार्टी है। इन सबने केवल और केवल अपने परिवार का भला किया। हमारा एक ही उद्देश्य है — सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास।

उन्होंने कहा कि सपा सरकार के समय उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बदहाल थी। माफिया का आतंक था। लूट, अपहरण उद्योग बन चुका था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली योगी आदित्यनाथ सरकार के समय माफिया जान बचाने के लिए सरेंडर कर रहे हैं। करोड़ों की सरकारी संपत्तियों को भू-माफियाओं के चंगुल से छुड़ाया गया है। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त राज्य बना है।

इटावा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 29 जनवरी, 2022 को उत्तर प्रदेश के इटावा में प्रभावी मतदाता संवाद बैठक को संबोधित किया। अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोलते हुए श्री नड्डा ने कहा कि जिन लोगों ने कभी किसानों का भला नहीं किया, वे लोग आजकल मुट्ठी में अनाज लेकर घूम रहे हैं। यूपी की जनता को अखिलेश यादव बताएं कि उन्होंने अपने पांच साल में उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए क्या किया? 2014 में कृषि बजट केवल 22,000 करोड़ रुपये का था, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सरकार में आज यह लगभग छह गुना बढ़कर 1.23 लाख करोड़ रुपये हो गया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ सरकार है जिसने प्रदेश के 86 लाख किसानों के लगभग 36,000 करोड़ रुपये का ऋण माफ किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हैं जो किसान सम्मान निधि के तहत देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों को अब तक 1.80 लाख करोड़ रुपये दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी ढाई करोड़ से अधिक किसान इससे लाभान्वित हुए हैं। गन्ना किसानों को हमारी डबल इंजन की सरकार ने पांच साल में 1.48 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया जो सपा और बसपा सरकार में किये गए कुल भुगतान से भी कहीं अधिक है।

शिकोहाबाद और हाथरस

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 30 जनवरी, 2022 को उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद और हाथरस में प्रभावी मतदाता संवाद बैठक को संबोधित किया। अखिलेश यादव पर हमला जारी रखते हुए श्री नड्डा ने कहा कि आज अखिलेश यादव मुफ्त बिजली का वादा कर रहे हैं। अरे, जो अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं दे पाया, वह मुफ्त बिजली क्या देगा? हमारी सरकार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को लगभग 42 लाख आवास दिया गया, लेकिन सपा की अखिलेश सरकार में भू-माफिया गरीबों की जमीन और घर पर कब्जा करते घूमते थे। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश से उद्योग का भी पलायन हो रहा था, लेकिन पिछले पांच वर्षों में उद्योग आ रहा है। जिनके कारण पिछली सरकार में उद्योगों का पलायन हो रहा था, आज वे जेल में हैं।

कोंच, उरई और माधोगढ़

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 04 फरवरी, 2022 को उत्तर प्रदेश के कोंच, उरई और माधोगढ़ में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया।

श्री नड्डा ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री श्री

नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली योगी आदित्यनाथ सरकार है जिसने उत्तर प्रदेश के विकास को एक नया आयाम दिया है। पहले उत्तर प्रदेश में केवल 15 मेडिकल कॉलेज थे, अब मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 59 हो गई है। उत्तर प्रदेश में दो-दो एम्स बने हैं, अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी स्थापित हुई है। पहले यहां केवल दो एयरपोर्ट होते थे, आज पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, 8 और एयरपोर्ट बन रहे हैं। जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। पिछले 5 वर्षों में 5 एक्सप्रेस-वे बनाए जा रहे हैं। यह एक्सप्रेस-वे सिर्फ सड़क नहीं, फोर-लेन और सिक्स-लेन हाइवे नहीं है बल्कि यह उत्तर प्रदेश के विकास की गंगा है।

हापुड़ और मुरादाबाद

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 05 फरवरी, 2022 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ और मुरादाबाद में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्रीजी ने लगभग 45 करोड़ लोगों के लिए बैंकों के दरवाजे खोले, जबकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1971 में हुआ था। 2014 तक देश के केवल लगभग तीन करोड़ लोग ही बैंकिंग से जुड़ पाए थे। कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री जी ने महिला जन-धन खाताधारकों के एकाउंट में तीन किस्तों में 1,500 रुपये पहुंचाए। हमारी सरकार ने देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, पिछड़ों के जीवन में उत्थान लाने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में लगभग 42 लाख घर बने हैं, जिसमें गैस कनेक्शन, बिजली, पानी और शौचालय का प्रबंध किया गया है। साथ ही, देश के लगभग 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ दिया गया। हमारी सरकार ने विकास को जन-जन तक पहुंचाया है। उज्ज्वला योजना के तहत उत्तर प्रदेश में डेढ़ करोड़ से अधिक गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया गया और स्वच्छ भारत अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में लगभग दो करोड़ इज्जत घर बनाए गए। सौभाग्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश में लगभग 80 लाख घरों में बिजली पहुंचाई गई। कोरोना काल में देश के हर नागरिक के दो वक्त की रोटी की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश के लगभग 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त राशन उपलब्ध करा रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में भी लगभग 15 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हुए हैं।

नोएडा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 5 फरवरी, 2022 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित प्रभावी मतदाता संवाद को संबोधित किया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रेरा की समस्या का समाधान करने का काम किया है। चुनाव बाद इसकी बाकी समस्या का भी संपूर्ण समाधान किया जाएगा। ■

'भाजपा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करती है'

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 6 फरवरी 2022 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी और डोईवाला में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया और उत्तराखंड की जनता से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक बार पुनः भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने सहसपुर में जनसंपर्क अभियान भी किया। डोईवाला के कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उपस्थित थे।

श्री नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश और उत्तराखंड के हर गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, युवा एवं महिलाओं तथा अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आने के बाद अब तक लगभग 45 करोड़ बैंक खाते केवल जन-धन योजना के माध्यम से ही खुल चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान देश के लगभग 20 करोड़ जन-धन महिला खाताधारकों के खाते में तीन किस्तों में 1,500 रुपये दिए गए। उत्तराखंड में भी लगभग 26.83 लाख महिलाओं के खाते में भी पैसे पहुंचाए गए। स्वच्छता अभियान के तहत उत्तराखंड में लगभग 5.22 लाख इज्जत घर बनाये गए, उज्ज्वला योजना के तहत 3.65 लाख गैस कनेक्शन दिए गए, सौभाग्य योजना के तहत लाखों घरों में बिजली पहुंचाई गई और किसान सम्मान निधि के तहत उत्तराखंड के लगभग 9 लाख किसानों को अब तक लगभग 1,400 करोड़ रुपये की सहायता पहुंचाई गई। आयुष्मान भारत के तहत देश के लगभग 55 करोड़ लोगों को मुफ्त हेल्थ कार्ड दिया गया है और उत्तराखंड में तो अलग से भी अटल आयुष्मान हेल्थ कवर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार है जिसमें सैन्य धाम बन रहे हैं और ओआरओपी भी इम्प्लीमेंट हुआ है जिससे उत्तराखंड के लगभग 1.16 लाख पूर्व सैनिक लाभान्वित हुए हैं। इस पर लगभग 42,000 करोड़ रुपये खर्च किये गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। लगभग 889 किमी लंबा चार धाम ऑल वेदर रोड लगभग 12,000 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ेगा।

उत्तरकाशी के विकास कार्यक्रमों को रेखांकित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि यहां लगभग 5,840 इज्जत घर बने हैं, किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 51,000 किसानों को लाभ दिया गया है। ■

भाजपा सरकार में विकास जन-जन तक पहुंचा : अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने मथुरा, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अतरौली, सहसवान, अनूपशहर, डिबाई, लोनी, गोरखपुर, बागपत और अमरोहा सहित अनेक क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित कर मतदाताओं से उत्तर प्रदेश में विकास की गति को और तेज करने, कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ करने और गरीब कल्याण की धारा बहाए रखने के लिए एक बार पुनः प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की योगी आदित्यनाथ सरकार बनाने की अपील की

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने 27 जनवरी, 2022 को उत्तर प्रदेश के मथुरा और ग्रेटर नोएडा में प्रभावी मतदाता संवाद किया। श्री शाह ने कहा कि सपा-बसपा के कालखंड ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर के रख दिया था। एक पार्टी आती थी तो एक जाति का विकास होता था, दूसरी पार्टी आती थी तो दूसरी जाति का विकास होता था। कभी भी उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण विकास का नक्शा किसी ने भी नहीं खींचा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार आने के बाद योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' की राजनीति शुरू हुई और विकास जन-जन तक घर-घर तक पहुंचा।

मुजफ्फरनगर और सहारनपुर

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने 29 जनवरी, 2022 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में आयोजित प्रभावी मतदाता संवाद को संबोधित किया। श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र, हर समाज के पूर्वजों का सम्मान करती है। सपा-बसपा सरकार में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर कुछ भी नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमने अलीगढ़ में उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय का निर्माण किया है। छपरौली-टांडा मार्ग को चौधरी चरण सिंह मार्ग, छपरौली-बरनावा मार्ग को महेंद्र सिंह टिकैत मार्ग और जोहड़ी बिजली घर से बिजवाड़ा रास्ते को शूटर दादी चन्द्रों के नाम पर नामकरण की स्वीकृति दी गई है। हरियाणा में बड़े किसान नेता सर छोटू रामजी की प्रतिमा स्थापित की गई है।

अतरौली और सहसवान

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने 2 फरवरी, 2022 को उत्तर प्रदेश के अतरौली (अलीगढ़) और सहसवान (बदायूं) में उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव के तहत जनसभा को संबोधित किया। श्री शाह ने कहा कि बाबू कल्याण सिंह के बताये रास्ते पर चलते हुए उत्तर प्रदेश में 2014, 2017 और 2019 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय मिली। ये बाबू कल्याण सिंहजी थे जिन्होंने सबसे पहले समाज का विभाजन किये बगैर पिछड़े समाज के अधिकार की बात की, पिछड़ा समाज को

अधिकार दिया और उनका सम्मान बढ़ाया। ये बाबू कल्याण सिंहजी थे जिन्होंने श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री पद से भी हंसते-हंसते त्यागपत्र दे दिया।

अनूपशहर, डिबाई और लोनी

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने 3 फरवरी, 2022 को उत्तर प्रदेश के अनूपशहर, डिबाई और लोनी में जनसभाओं को संबोधित किया। सपा-बसपा पर बरसते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली योगी आदित्यनाथ सरकार में रिकॉर्ड मात्रा में धान और गेहूं की एमएसपी पर खरीद हो रही है। देश के 11 करोड़ से अधिक किसानों को हर साल किसान सम्मान निधि के तहत श्री नरेन्द्र मोदी सरकार की ओर से 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। उत्तर प्रदेश में भी लगभग ढाई करोड़ किसानों को इसका फायदा हो रहा है। गन्ना किसानों को सर्वाधिक भुगतान डबल इंजन की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिया है।

बागपत और अमरोहा

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने 6 फरवरी, 2022 उत्तर प्रदेश के बागपत और अमरोहा में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया। श्री शाह ने कहा कि सपा-बसपा के 15 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश देश की सातवें स्थान की अर्थव्यवस्था थी, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में और योगी आदित्यनाथ की योजनाओं से आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। ■

'कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबों के लिए कभी भी कुछ नहीं किया'

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने 28 जनवरी, 2022 को उत्तराखंड चुनाव प्रचार की शुरुआत रुद्रप्रयाग में भगवान् रुद्रनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना के साथ की। इसके पश्चात् उन्होंने रुद्रप्रयाग के जिला भाजपा कार्यालय में भूतपूर्व सैनिकों, महिला समूहों एवं अनुसूचित जाति समाज के साथ बैठकें की और उनसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व विकास के प्रति समर्पित डबल इंजन की भाजपा सरकार को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील की।

आदरणीय जनरल बिपिन रावतजी को श्रद्धांजलि देते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि जनरल बिपिन रावतजी ने देश के लिए अपना बलिदान दिया। श्री शाह ने देहरादून में बन रहे सैन्य धाम की चर्चा करते हुए कहा कि उत्तराखंड के लगभग 1,734 शहीद परिवारों के घरों से लायी गई मिट्टी से देहरादून में सैन्य धाम बनाया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हैं जिन्होंने सत्ता में आने के साथ ही 1972 से चली आ रही भूतपूर्व सैनिकों की 'वन रैंक — वन पेंशन' की मांग को पूरा किया। लगभग 20 लाख सैनिकों को इस योजना का लाभ मिल रहा है।

मातृशक्ति कल्याण संबंध में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्रीजी ने सरकार चलाने के साथ-साथ जनजागृति भी चलाई और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जिसके फलस्वरूप आज लड़कों और लड़कियों का जन्म-दर लगभग बराबर की ओर पहुंच रहा है। हमारी सरकार आने से पहले 100 में से 50 प्रसव ही इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होता था, जबकि ये संख्या आज हमारी सरकार में यह संख्या 100 में 89 तक पहुंच गई है। मुद्रा योजना के तहत देश भर में लगभग 70 प्रतिशत महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया गया।

दलितों-पिछड़ों के कल्याण के लिए श्री नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा किये गए कार्यों को रेखांकित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबों के लिए कभी भी कुछ नहीं किया। देश भर में लगभग 8 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए जिसमें से सबसे अधिक कनेक्शन दलितों और पिछड़ों को लाभ हुआ। मुद्रा योजना के तहत देश भर में जितने ऋण उपलब्ध कराये गए उसमें से लगभग 50 प्रतिशत मुद्रा ऋण अनुसूचित समाज के भाई-बहनों को दिया गया है।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड की डबल इंजन की सरकार में प्रदेश में लगभग 4.25 लाख घरों में फ्री ऑफ कॉस्ट गैस कनेक्शन पहुंचाया गया। कोरोना काल खंड में उत्तराखंड के लगभग 15 लाख परिवारों को दो साल से हर गरीब को मुफ्त खाद्यान्न मुहैया कराया जा रहा है। लगभग 9 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि योजना से फायदा मिल रहा है। उत्तराखंड में लगभग दो लाख लोगों को मुद्रा योजना से लाभ पहुंचा है। ■

'भाजपा के 10 वर्षों के शासनकाल में विकास के एक नए युग की शुरुआत हुई है'

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने 30 जनवरी, 2022 को गोवा के पोण्डा और संवोर्देम में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया और जनता से गोवा में विकास की गति बनाये रखने एवं भ्रष्टाचार-मुक्त पारदर्शी शासन व्यवस्था के लिए एक बार पुनः प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की अपील की।

कांग्रेस पर हमला करते हुए श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस की दिगंबर कामत सरकार श्री 'A' के लिए जानी जाती थी। श्री A का मतलब है - अव्यवस्था, अस्थिरता और अराजकता व भ्रष्टाचार। इस श्री 'A' ने गोवा को तबाह करके रख दिया था। भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्षों के शासन काल में गोवा में विकास के एक नए युग की शुरुआत हुई है।

गोवा के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बोलते हुए श्री शाह ने कहा कि गोवा में लगभग 3,000 करोड़ रुपये की लागत से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, लगभग 2700 करोड़ रुपये की लागत से न्यू जुआरी ब्रिज बन रहा है, अटल सेतु का निर्माण हो रहा है, कई और ब्रिज बन रहे हैं।

श्री शाह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियों का घोषणापत्र केवल झूठ का पुलिंदा होता है, जबकि हमारे लिए हमारा घोषणापत्र विकास का रोडमैप होता है। गोवा की प्रमोद सावंत सरकार ने भाजपा के घोषणापत्र के लगभग 92.8 प्रतिशत वादे पूरे कर दिए हैं। भाजपा जो कहती है, वह करती है। यह हमने पांच साल में करके दिखाया है। यदि विपक्षी पार्टियों की हॉचपॉच की सरकार बनी तो गोवा में फिर से अराजकता और भ्रष्टाचार का बोलबाला होगा तथा अस्थिरता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि पोंडा में लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से पुल बनाया जा रहा है, बाईपास बनाया गया है, क्रांति मैदान का जीर्णोद्धार किया गया है, कला मंदिर का नवीनीकरण हो रहा है, आवास योजना के तहत लगभग 160 गरीबों के घर यहां बने हैं, उजाला योजना के तहत लगभग हजारों बल्ब वितरित किये गए हैं और साढ़े तीन हजार से अधिक विधवाओं को 2,500 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता दी जा रही है। जल जीवन-मिशन के तहत 2.40 लाख परिवारों को शुद्ध पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। सौभाग्य योजना के तहत 1.28 लाख परिवारों के घरों में बिजली पहुंचाने का काम आजादी के बाद पहली बार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गोवा में कई नए कॉलेज बने, व्यावसायिक संस्थानों की संख्या 31 से बढ़कर 67 पहुंची। पुलिस की संख्या में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भाजपा की प्रमोद सावंत सरकार में गोवा में अपराध दर में लगभग 50 प्रतिशत की कटौती हुई। ■

भारतीय अर्थव्यवस्था की 2021-22 में 9.2 प्रतिशत की भारी वृद्धि

31 दिसंबर, 2021 को विदेशी मुद्रा भंडार 634 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जो 13 महीनों से अधिक के आयात के समतुल्य और देश के विदेशी ऋण से अधिक है

केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती सीतारमण ने 31 जनवरी को संसद में आर्थिक समीक्षा 2021-22 प्रस्तुत किया। आर्थिक समीक्षा में कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2021-22 में 9.2 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि दर्ज करेगी। इसमें 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर 8.0-8.5 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है।

आर्थिक समीक्षा के अनुसार कृषि क्षेत्र में पिछले वर्ष 3.6 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2021-22 में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि दर संभावित है। औद्योगिक क्षेत्र में 2020-21 के दौरान 7 प्रतिशत की विकास दर तेजी से बढ़कर 2021-22 में 11.8 प्रतिशत होने का अनुमान है। सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 2021-22 में 8.2 प्रतिशत रहेगी।

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि 31 दिसंबर, 2021 को विदेशी मुद्रा भंडार 634 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जो 13 महीनों से अधिक के आयात के समतुल्य और देश के विदेशी ऋण से अधिक है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 की मुख्य बातें निम्न हैं:

अर्थव्यवस्था की स्थिति

- 2020-21 में 7.3 प्रतिशत की गिरावट के बाद 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 9.3 प्रतिशत (पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार) बढ़ने का अनुमान है।
- 2022-23 में जीडीपी की विकास दर 8-8.5 प्रतिशत रह सकती है।
- आर्थिक पुनरुद्धार को समर्थन देने के लिए आने वाले साल में वित्तीय प्रणाली के साथ निजी क्षेत्र के निवेश में बढ़ोतरी की संभावना है।
- 2022-23 के लिए यह अनुमान विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक की क्रमशः 8.7 और 7.5 प्रतिशत रियल टर्म जीडीपी विकास की संभावना के अनुरूप है।
- आईएमएफ के ताजा विश्व आर्थिक परिदृश्य अनुमान के तहत 2021-22 और 2022-23 में भारत की रियल जीडीपी विकास दर 9 प्रतिशत और 2023-24 में 7.1 प्रतिशत रहने की संभावना है, जिससे भारत अगले तीन साल तक दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बनी रहेगी।
- 2021-22 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के 3.9 प्रतिशत; उद्योग के 11.8 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र के 8.2 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

राजकोषीय मजबूती

- 2021-22 बजट अनुमान (2020-21 के अनंतिम आंकड़ों की तुलना में) 9.6 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि की तुलना में केन्द्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां (अप्रैल-नवम्बर, 2021) 67.2 प्रतिशत तक बढ़ गईं।
- सालाना आधार पर अप्रैल-नवम्बर, 2021 के दौरान सकल कर-राजस्व में 50 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह 2019-20 के महामारी से पहले के स्तरों की तुलना में भी बेहतर प्रदर्शन है।
- अप्रैल-नवम्बर, 2021 के दौरान बुनियादी ढांचे से जुड़े क्षेत्रों पर जोर के साथ पूंजी व्यय में सालाना आधार पर 13.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

बाह्य क्षेत्र

- भारत के वाणिज्यिक निर्यात एवं आयात ने दमदार वापसी की और चालू वित्त वर्ष के दौरान यह कोविड से पहले के स्तरों से ज्यादा हो गया।
- 2021-22 की पहली छमाही में विदेशी मुद्रा भंडार 600 बिलियन डॉलर से ऊपर निकल गया और यह 31 दिसम्बर, 2021 तक 633.6 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया।
- नवम्बर, 2021 के अंत तक चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत चौथा सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश था।

मौद्रिक प्रबंधन

- प्रणाली में तरलता अधिशेष रही।
- 2021-22 में रेपो दर 4 प्रतिशत पर बनी रही।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने और अधिक तरलता प्रदान करने के लिए जी-सेक अधिग्रहण कार्यक्रम तथा सामाजिक दीर्घकालिक रेपो संचालन जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

पूंजी बाजारों के लिए असाधारण वर्ष

- अप्रैल-नवंबर, 2021 में 75 प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) से 89,066 करोड़ रुपये उगाहे गए, जो पिछले एक दशक के किसी भी वर्ष में सबसे अधिक है।
- 18 अक्टूबर, 2021 को सेंसेक्स और निफ्टी 61,766 तथा 18,477 की ऊंचाई पर पहुंचे।
- प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्था में भारतीय बाजारों ने अप्रैल-दिसंबर, 2021 में समकक्ष बाजारों से अच्छा प्रदर्शन किया।

मूल्य तथा मुद्रास्फीति

- औसत शीर्ष सीपीआई-संयुक्त मुद्रास्फीति 2021-22 (अप्रैल-

दिसंबर) में सुधरकर 5.2 प्रतिशत हुई, जबकि 2020-21 की इसी अवधि में यह 6.6 प्रतिशत थी।

- खुदरा स्फीति में गिरावट खाद्य मुद्रास्फीति में सुधार के कारण आई।
- 2021-22 (अप्रैल से दिसंबर) में औसत खाद्य मुद्रास्फीति 2.9 प्रतिशत के निम्न स्तर पर रही, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 9.1 प्रतिशत थी।

सतत विकास तथ जलवायु परिवर्तन

- भारत, विश्व में दसवां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है।
- 2010 से 2020 के दौरान वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में 2020 में भारत का विश्व में तीसरा स्थान रहा।
- 2020 में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कवर किए गए वन 24 प्रतिशत रहे, यानी विश्व के कुल वन क्षेत्र का 2 प्रतिशत।
- गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के तटों पर अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) की अनुपालन स्थिति 2017 के 39 प्रतिशत से सुधरकर 2020 में 81 प्रतिशत हो गई।

कृषि तथा खाद्य प्रबंधन

- पिछले दो वर्षों में कृषि क्षेत्र में विकास देखा गया। देश के कुल मूल्यवर्धन (जीवीए) में महत्वपूर्ण 18.8 प्रतिशत (2021-22) की वृद्धि हुई, इस तरह 2020-21 में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 2021-22 में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- पशुपालन, डेयरी तथा मछलीपालन सहित संबंधित क्षेत्र तेजी से उच्च वृद्धि वाले क्षेत्र के रूप में तथा कृषि क्षेत्र में सम्पूर्ण वृद्धि के प्रमुख प्रेरक के रूप में उभर रहे हैं।
- 2019-20 में समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों में पशुधन क्षेत्र 8.15 प्रतिशत के सीएजीआर पर बढ़ा रहा।
- भारत विश्व का सबसे बड़ा खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम चलाता है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी योजनाओं के माध्यम से खाद्य सुरक्षा नेटवर्क कवरेज का और अधिक विस्तार किया है।

उद्योग और बुनियादी ढांचा

- अप्रैल-नवम्बर, 2021 के दौरान औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (आईआईपी) बढ़कर 17.4 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) हो गया। यह अप्रैल-नवम्बर, 2020 में (-)15.3 प्रतिशत था।
- भारतीय रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय 2009-2014 के दौरान 45,980 करोड़ रुपये के वार्षिक औसत से बढ़कर 2020-21 में 155,181 करोड़ रुपये हो गया और 2021-22 में इसे 215,058 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का बजट रखा गया है। इस प्रकार इसमें 2014 के स्तर की तुलना में पांच गुना बढ़ोतरी हुई है।
- वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन सड़क निर्माण की सीमा को बढ़ाकर 36.5 किलोमीटर प्रतिदिन कर दिया गया है जो 2019-20 में 28 किलोमीटर प्रतिदिन थी, इस प्रकार इसमें 30.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है।
- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के शुभारंभ से लेनदेन लागत घटाने और व्यापार को आसान बनाने के कार्य में सुधार लाने के उपायों के साथ-साथ डिजिटल और वस्तुगत दोनों बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिला है, जिससे रिकवरी की गति में मदद मिलेगी।

सेवाएं

- जीवीए की सेवाओं ने वर्ष 2021-22 की जुलाई-सितम्बर तिमाही में पूर्व-महामारी स्तर को पार कर लिया है।
- समग्र सेवा क्षेत्र जीवीए में 2021-22 में 8.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
- अप्रैल-दिसम्बर, 2021 के दौरान रेल मालभाड़ा ने पूर्व-महामारी स्तर को पार कर लिया है, जबकि हवाई मालभाड़ा और बंदरगाह यातायात लगभग अपने पूर्व-महामारी स्तरों तक पहुंच गये हैं। हवाई और रेल यात्री यातायात में धीर-धीरे वृद्धि हो रही है जो यह दर्शाता है कि महामारी की पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर का प्रभाव कहीं अधिक कम था।
- आईटी-बीपीएम सेवा राजस्व 2020-21 में 194 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। इस अवधि के दौरान इस क्षेत्र में 1.38 लाख कर्मचारी शामिल किए गए।
- भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम बन गया है। नये मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स की संख्या 2021-22 में बढ़कर 14 हजार से अधिक हो गई है जो 2016-17 में केवल 735 थी।
- 44 भारतीय स्टार्ट-अप्स ने 2021 में यूनिकॉर्न दर्जा हासिल किया। इससे यूनिकॉर्न स्टार्ट-अप्स की कुल संख्या 83 हो गई है और इनमें से अधिकांश सेवा क्षेत्र में हैं।

सामाजिक बुनियादी ढ़ांचा और रोजगार

- अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान से रोजगार सूचकांक वर्ष 2020-21 की अंतिम तिमाही के दौरान वापस पूर्व-महामारी स्तर पर आ गए हैं।
- मार्च, 2021 तक प्राप्त तिमाही आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएफएलएस) आंकड़ों के अनुसार महामारी के कारण प्रभावित शहरी क्षेत्र में रोजगार लगभग पूर्व महामारी स्तर तक वापस आ गये हैं।
- सामाजिक सेवाओं (स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य) पर जीडीपी के अनुपात के रूप में केन्द्र और राज्यों का व्यय जो 2014-15 में 6.2 प्रतिशत था; 2021-22 (बजट अनुमान) में बढ़कर 8.6 प्रतिशत हो गया।
- जल जीवन मिशन के तहत 83 जिले 'हर घर जल' जिले बन गए हैं। ■

सिद्धांत और नीतियां

पं. दीनदयाल उपाध्याय

जनवरी, 1965 में विजयवाड़ा में जनसंघ के बारहवें सार्वदेशिक अधिवेशन में स्वीकृत दस्तावेज

(गतांक से...)

आदेवमातृका कृषि

सिंचाई की योग्य व्यवस्था करना भारतीय शासन का सदैव से ध्येय रहा है। कृषि को आदेवमातृका बनाना शास्त्रों आदेश है। स्वातंत्र्योत्तर काल में यद्यपि बड़े-बड़े बांधों के अनेक कार्यक्रम हाथ में लिये गए हैं, फिर भी अधिकांश कृषि इंद्रदेव की कृपा पर ही निर्भर है। छोटी योजनाओं की ओर दुर्लक्ष्य हुआ है। पुराने कुएं, तालाब, पोखरे आदि मरम्मत के अभाव में बेकार हो गए हैं।

सर्वतोमुखी दृष्टि से विचार किया जाए तो भारत के लिए छोटे-छोटे सिंचाई के साधन ही उपयुक्त हैं। बड़े बांध पूंजी-प्रधान हैं। देश के अनेक भू-भागों में भूमि और जल-तल की ऐसी स्थिति है कि बड़े बांधों के कारण सेम और भूक्षार उत्पन्न होता है, जिससे भूमि के अनुर्वरा होने की आशंकाएं हैं। विद्यमान योजनाओं को छोड़कर आगे सामान्यतया छोटी योजनाएं ही हाथ में लेनी चाहिए। बड़ी योजनाओं में लगी पूंजी की शीघ्र वसूली की चिंता में सिंचाई एवं अन्य करों की दरें ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिससे किसान उन्हें दुर्वह समझकर सिंचाई के साधनों का उपयोग ही न करें। छोटी योजनाओं में नलकूप बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

सर्वतोमुखी दृष्टि से विचार किया जाए तो भारत के लिए छोटे-छोटे सिंचाई के साधन ही उपयुक्त हैं। बड़े बांध पूंजी-प्रधान हैं। देश के अनेक भू-भागों में भूमि और जल-तल की ऐसी स्थिति है कि बड़े बांधों के कारण सेम और भूक्षार उत्पन्न होता है, जिससे भूमि के अनुर्वरा होने की आशंकाएं हैं

भूधृति

कृषि उत्पादन का संबंध कृषक से भी होता है। खेत और खेतिहर इन दोनों का एक अविभाज्य संबंध है। भूमि में सुधार करने तथा अधिकाधिक श्रम से अधिकतम उत्पादन करने के लिए यह आवश्यक है कि किसान को इस बात का विश्वास हो कि वह भूमि से हटाया नहीं जाएगा तथा पैदा की हुई फसल का अधिकांश भाग उसका अपना ही होगा। विभिन्न ऐतिहासिक कारणों से भारत की भूमि व्यवस्था में बहुत से मध्यस्थों का समावेश हो गया है। जमींदार और जागीरदार अब समाप्त कर दिए गए हैं, किंतु रैयतवारी प्रथा के अंतर्गत भी ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं, जो स्वयं खेती नहीं करते, बल्कि दूसरों को पट्टे पर देकर उनसे फसल का निश्चित भाग लेते रहते हैं। कानून में वे कृषक हैं और कृषि के नाम पर मिलनेवाली सुविधाएं उन्हें ही प्राप्त होती हैं। फलतः वास्तविक कृषक निर्धन एवं सुविधाहीन बना हुआ है। कृषि विकास के लिए आवश्यक है कि वास्तविक किसान को भूमि का मालिक बनाया जाए। कुछ राज्यों में, जहां इस प्रकार के क़ानून बने हैं, उनका ठीक-ठीक पालन नहीं हुआ। गैर-कानूनी, बेदखली या मरती से खेत छोड़ने के मामले बहुत ज्यादा है। आवश्यकता है कि काग़ज़ों में सुधार हो तथा कानून की भावना के अनुसार उसका पालन हो।

जोतने वाले की भूमि

व्याख्या—'जोतनेवाले की भूमि' का यह अर्थ कदापि नहीं कि अपनी मेहनत को छोड़कर किसान किसी दूसरे की सेवाओं से लाभ नहीं उठा सकता। उसे आवश्यकतानुसार मजदूर रख सकने का अधिकार होना चाहिए, अन्यथा खेती चौपट हो जाएगी। 'जोतनेवाले' का साधारण अर्थ यही हो सकता है कि वह खेती के हानि-लाभ के लिए उत्तरदायी हो, उसमें पूंजी लगाता हो, वहां परिश्रम करता हो तथा उसकी देखभाल करता हो।

ऐसी अवस्थाएं भी हो सकती हैं, जब किसी कारणवश किसान एक या दो वर्ष के लिए खेती न कर सकता हो। यदि उस अवस्था में वह अपनी ज़मीन दूसरों को कुछ समय के लिए खेती करने के लिए नहीं दे सकेगा तो वह या तो खेत को बिना बोए हुए छोड़ देगा या केवल कागजी कार्रवाई के लिए उस पर खेती करेगा। इसका परिणाम कृषि उत्पादन के गिरने के रूप में होगा। अतः हमें

कुछ अपवाद अवश्य करने होंगे। अवयस्कों, विधवाओं, अपंगों तथा फ़ौज के लोगों को भी इस नियम से मुक्त रखना होगा।

इसी प्रकार अलाभकर जोत वाले किसानों को अपना खेत पट्टे पर देने और लेने का अधिकार होना चाहिए।

अधिकतम जोत

सघन खेती की अनिवार्यता के कारण हमें एक और आर्थिक जोतों की व्यवस्था करनी होगी तथा दूसरी ओर जोत की अधिकतम मर्यादाएं भी बांधनी होंगी।

कृषि स्वामित्व

सहकारी या सामुदायिक खेती भारत के भूमि-जन अनुपात, प्रजातंत्रीय पद्धति, बेकारी का निवारण, प्रति एकड़ अधिकतम उत्पादन, कृषि में मानकों के निर्धारण की असंभवनीयता, किसान का भूमि-प्रेम एवं हमारे जीवन-मूल्य, इन सभी दृष्टियों से हमारे लिए अनुपयुक्त है। कृषक स्वामित्व ही भूमि व्यवस्था का आधार होना चाहिए।

चकबंदी

भूमि का अंतर्विभाजन एवं अपखंडन भी भारतीय कृषि की एक समस्या है। इसे चकबंदी द्वारा रोकने के प्रयास किए गए हैं। जिन तरीक़ों और क़ानूनों के अंतर्गत चकबंदी की जा रही है, उनमें पक्षपात एवं भेदभाव के लिए बहुत गुंजाइश है। गांव का मास्टर प्लान बनाकर चकबंदी करनी चाहिए। जिनके चक छोटे हैं, उन्हें भूमि देते समय यह ध्यान रखा जाए कि वे उन्हें लाभकर बना सकें।

आर्थिक जोत से नीचे अंतर्विभाजन और अपखंडन पर रोक लगा दी जाए।

खेतिहर मज़दूर

कृषि में खेतिहर मजदूर का सहयोग सदैव आवश्यक रहेगा। उसको पूरी मजदूरी, वर्ष भर काम तथा ग्रामवासियों को मिलनेवाली सभी सुविधाएं मिल सकें, इसकी व्यवस्था करनी होगी। इस हेतु गांवों में सहायक उद्योगों की स्थापना आवश्यक है।

गोवंश की अवध्यता

गोवंश के प्रति भारतीय जनता की भावनाओं का समादर करने तथा उसका भारत की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान होने के कारण उसके संरक्षण एवं संवर्धन पर अत्यधिक बल देना चाहिए तथा गोवंश हत्या पर वैधानिक प्रतिबंध लगाना चाहिए। मिश्रित कृषि भारत के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

विपणन

उत्पादन वृद्धि के कार्यक्रमों के साथ ही कृषि माल के विपणन एवं ऋण की व्यवस्था भी करनी होगी। अभी तक गांव का साहूकार कुछ अंशों में ये कार्य करता है। किंतु बाजारों की अच्छी व्यवस्था न होने के कारण किसान को कभी उचित दाम नहीं मिल पाया है। कच्चे माल के कम दामों के लिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था ही मूलतः दोषी है। इसमें कच्चे माल और पक्के माल के मूल्यों के बीच कोई तालमेल नहीं। अतः किसान के साथ न्याय करने के लिए आवश्यक है कि गांवों में कोठार एवं गोदाम बनाए जाएं, जिससे किसान को अपनी फसल की साख पर योग्य ऋण प्राप्त हो जाएं। सहकारी समितियां यह काम भली-भांति कर सकती हैं। कृषि बीमा योजना भी उपयोगी सिद्ध होगी।

वन देश की बहुमूल्य संपत्ति हैं। उनका प्रभाव देश की जलवायु एवं वर्षा पर भी पड़ता है। उनका ह्रास रोकने, संरक्षण एवं रोपण के लिए वैज्ञानिक आधार पर कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। वन और वनवासी दोनों ही पिछले अनेक वर्षों से बुरी तरह शोषण के शिकार हुए हैं। वनवासी को खेती के लिए भूमि देना तथा वनों से आजीविका चलाने की सुविधा पुनः देना आवश्यक है

वन

वन देश की बहुमूल्य संपत्ति हैं। उनका प्रभाव देश की जलवायु एवं वर्षा पर भी पड़ता है। उनका ह्रास रोकने, संरक्षण एवं रोपण के लिए वैज्ञानिक आधार पर कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। वन और वनवासी दोनों ही पिछले अनेक वर्षों से बुरी तरह शोषण के शिकार हुए हैं। वनवासी को खेती के लिए भूमि देना तथा वनों से आजीविका चलाने की सुविधा पुनः देना आवश्यक है।

उद्योग नीति

देश के औद्योगीकरण की अपरिहार्यता निर्विवाद है, किंतु उसकी गति कितनी और स्वरूप कैसा हो, यह मतभेद का विषय है। सामान्यतः पश्चिम के औद्योगिक ढांचे को ही एकमेव ढांचा मानकर उसे जल्दी-से-जल्दी देश में लाने की आतुरता दिखती है। विदेशी पूंजी के सहयोग ने इस निर्णय को और भी प्रभावित किया है। अभी तक इस प्रकार का जो औद्योगीकरण हुआ है, उसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि हुई है, किंतु दूसरी और पुराने उद्योग नष्ट होकर निरुद्योगीकरण एवं विपूंजीकरण हुआ है, बेकारी बढ़ी है, विदेशों पर निर्भरता तथा विदेशी ऋण में वृद्धि हुई है, केंद्रीयकरण तथा आर्थिक विषमताएं अधिक हुई हैं तथा तेजी से होनेवाले नगरीकरण एवं अपने घर और गांव से दूर बड़े-बड़े शहरों में समाज-संबंध-विहीन जनसमुदाय के केंद्रीकरण से अनेक समस्याएं पैदा हुई हैं। हम इन समस्याओं को औद्योगीकरण के स्वाभाविक परिणाम कहकर नहीं टाल सकते। ■

(क्रमशः...)

नहीं रहीं भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर

'भारत की स्वर कोकिला' लता मंगेशकर जी नहीं रहीं। 6 फरवरी, 2022 को 92 वर्ष की आयु में मुंबई में उनका निधन हो गया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मुंबई में भारत रत्न स्व. लता मंगेशकर को अंतिम श्रद्धांजलि दी। भारत सरकार ने दिवंगत गायिका की याद में दो दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। 6 फरवरी से 7 फरवरी तक राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उनके परिवार से बात कर, अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा, "मेरी पीड़ा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दयालु और देखभाल करने वाली लता दीदी हमें छोड़कर चली गई हैं। वह देश में एक खालीपन छोड़ गई है जिसे भरा नहीं जा सकता। आने वाली पीढ़ियां

उन्हें भारतीय संस्कृति की एक महान विभूति के रूप में याद करेंगी, जिनकी सुरीली आवाज में लोगों को मंत्रमुग्ध करने की अद्वितीय क्षमता थी।"

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, "आज हमारी आदरणीय दीदी लता जी हम सब के बीच नहीं रहीं। मैं अपनी ओर से और हम सभी की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान दें, उनकी आत्मा को शांति दें और परिवार के सभी सदस्यों को इस दुःख को सहने की शक्ति दें।"

केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह और श्री नितिन गडकरी ने भी महान गायिका के निधन पर शोक व्यक्त किया।

2001 में लता मंगेशकर जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1999 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने 30 से ज्यादा भाषाओं में गाने गाये हैं। ■

चंदूपतला जंग रेड्डी का निधन

तेलंगाना भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद श्री चंदूपतला जंग रेड्डी का 5 फरवरी, 2022 को 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। श्री रेड्डी का जन्म 18 नवंबर, 1935 को हुआ था। उन्होंने आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में स्थित परकला गांव में एक शिक्षक के रूप में दस वर्षों तक कार्य किया। वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। वह 1967-72 में (पारकल से जनसंघ के सदस्य के रूप में), 1978-83 (श्यामपेट से जनता पार्टी के सदस्य के रूप में) और 1983-84 (श्यामपेट से भाजपा के सदस्य के रूप में) आंध्र प्रदेश विधान सभा सदस्य बने। उन्हें 1984 में 8वीं लोकसभा में संसद सदस्य के तौर पर याद किया जाता है। उस वर्ष, भारतीय जनता पार्टी ने 543 संसदीय क्षेत्रों में से केवल दो पर जीत हासिल की; जिसमें से एक को तत्कालीन अविभाजित आंध्र प्रदेश में हनमकोंडा का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री चेन्दुपतला जंग रेड्डी ने जीता था, और दूसरी सीट मेहसाणा, गुजरात थी, जिस पर श्री एके पटेल विजयी हुए। उन्होंने तेलंगाना सत्याग्रह आंदोलन और केरल में मलापुम जिला विरोधी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। उन्हें 1970 में बांग्लादेश को मान्यता देने की मांग कर रहे समूह का नेतृत्व करने के लिए दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था, और 14 नवंबर, 1975 से 18 दिसंबर, 1976 तक आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा) के तहत कैद में रखा गया।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, "वयोवृद्ध जनसंघ और भाजपा नेता श्री सी. जंग रेड्डी जी के निधन से दुःखी हूं।" उन्होंने पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। देश और पार्टी की सेवा की उनकी प्रेरणादायी यात्रा को भुलाया नहीं जा सकेगा। ■

'हम पंजाब की शांति, सुरक्षा और समृद्धि चाहते हैं'

भाजपा 65, पंजाब लोक कांग्रेस 37 और संयुक्त अकाली दल 15 सीटों पर लड़ेगी चुनाव

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 24 जनवरी 2022 को भाजपा के केन्द्रीय कार्यालय में आयोजित एक प्रेस-वार्ता में पंजाब की भाजपा-नीत गठबंधन की सीट शेयरिंग की घोषणा की और कहा कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी, पंजाब लोक कांग्रेस और संयुक्त अकाली दल, तीनों एक साथ मिलकर विधान सभा चुनाव लड़ रहे हैं जिसमें भाजपा 65 विधान सभा सीटों, पंजाब लोक कांग्रेस 37 और संयुक्त अकाली दल 15 विधान सभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

श्री नड्डा ने कहा कि आज पंजाब की स्थिति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एक प्रोग्रेसिव स्टेट होने के बावजूद पंजाब आज लगभग तीन लाख करोड़ रुपये के कर्ज में डूबा हुआ है। डेवलपमेंट इंडेक्स में पंजाब लगातार नीचे की ओर खिसकता जा रहा है। हमारे गठबंधन का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि पंजाब को पुनः विकास के रास्ते पर कैसे तेज गति से अग्रसर किया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का पंजाब के प्रति एक विशेष प्यार और लगाव रहा है। प्रधानमंत्रीजी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। यह गुरु गोबिंद सिंहजी के साहिबजादे, साहिबजादे जोरावर सिंह और साहिबजादे फतेह सिंह के अद्भुत शौर्य एवं बलिदान को देश की ओर से दी जाने वाली भावभीनी श्रद्धांजलि है।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जो कार्य सिख भाइयों के लिए किया है, वह हम सबके लिए बहुत ही गर्व का विषय है। श्री श्री हरमंदिर साहिब को फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने का पहले कोई प्रावधान नहीं था लेकिन प्रधानमंत्रीजी की प्रेरणा से एफसीआरए रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ और अब श्री श्री हरमंदिर साहिब को विदेशी योगदान मिलना शुरू हो गया है। यह कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के समय में हुआ जबकि कई सिख भाई भी शासन में आये थे लेकिन ये कार्य न हो सका। पहले लंगर पर भी टैक्स लगता था, इसे टैक्स फ्री करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। आजादी से लेकर 70 सालों तक डेरा नानक साहब और करतारपुर साहिब का दर्शन करने का अवसर हमारे सिख भाइयों को नहीं मिल पाया था लेकिन प्रधानमंत्रीजी की प्रेरणा से 120 करोड़ रुपये की निधि से यह कॉरिडोर बन कर तैयार हुआ और सिख भाइयों को डेरा नानक साहब और करतारपुर साहिब का दर्शन करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। सुल्तानपुर-लोधी रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया गया है, स्पेशल ट्रेंस चलाई गई। इंटरफेथ स्टडीज को बढ़ावा देते हुए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में नेशनल इंस्टीटयूट फॉर इंटरफेथ स्टडीज की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर पूरे देश में 350वें

प्रकाश पर्व को पूरे धूमधाम से मनाया गया। जामनगर में एक 750 बेड वाला अस्पताल भी बनाया गया।

उन्होंने कहा कि चाहे जलियांवाला बाग़ का जीर्णोद्धार एवं उसका आधुनिकीकरण हो, सिख भाइयों को ब्लैकलिस्ट से हटाने की मांग हो या 1984 में हुए सिख नरसंहार के दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना, ये सारे कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव हुआ है।

श्री नड्डा ने कहा कि पंजाब की सुरक्षा हमारी मुख्य प्राथमिकता है। जिस तरह से पंजाब में सुरक्षा के विषय के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसकी हम सभी कड़ी निंदा करते हैं। माफिया राज ने पंजाब को खोखला करके रख दिया है। पंजाब में हमारी सरकार आने पर हर तरह के माफिया राज को ख़त्म करेंगे और माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा, पंजाब लोक कांग्रेस और संयुक्त अकाली दल- हम सब पंजाब की शांति, सुरक्षा और समृद्धि चाहते हैं। इसलिए हम तीनों दल जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म में यकीन रखते हैं।

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष एवं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि हम तीनों पार्टियों ने पंजाब में शांति, सुरक्षा, समृद्धि और पंजाब के लोगों की खुशहाली के लिए गठबंधन का निर्णय लिया है। संयुक्त अकाली दल के अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह ढींढसा ने कहा कि पंजाब की हवा में जो जहर घोला जा रहा है, इस माहौल को ठीक करने के लिए हमने यह गठबंधन किया है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आभारी हूं कि उन्होंने पंजाब के विकास के लिए और सिख समुदाय के जीवन में बदलाव लाने के लिए कई कार्य किये हैं और कई कदम उठाये हैं। इस प्रेस वार्ता में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री अश्विनी शर्मा, पंजाब के चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप पुरी, केंद्रीय मंत्री श्री सोम प्रकाश तथा भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख एवं राज्य सभा सांसद श्री अनिल बलूनी भी उपस्थित थे। ■

राष्ट्रपति अभिभाषण: टीकाकरण, किसान कल्याण, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण पर जोर

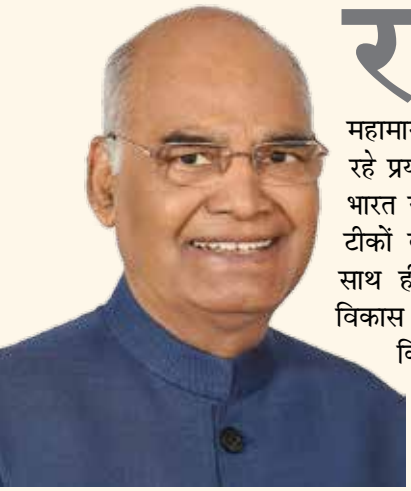

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 31 जनवरी, 2022 को कोरोना वायरस महामारी के मुकाबले के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते कहा कि भारत ने रिकॉर्ड समय में कोविड रोधी टीकों की 150 करोड़ खुराक लगाईं। साथ ही, उन्होंने कृषि क्षेत्र के सतत विकास के लिए देश के 80 प्रतिशत छोटे किसानों का आभार जताते हुए रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

संसद के बजट सत्र के पहले दिन केंद्रीय कक्ष में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में महिला सशक्तिकरण के प्रयासों के तहत विवाह के लिए महिलाओं की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष किये जाने की पहल का भी उल्लेख किया।

श्री कोविंद ने कहा कि कोरोना वायरस से उत्पन्न वैश्विक महामारी का यह तीसरा वर्ष है। इस दौरान हमने भारत के लोगों की लोकतांत्रिक मूल्यों में अगाध आस्था, अनुशासन और कर्तव्य-परायणता को और मजबूत होते देखा है। आज जब भारत, अपनी आजादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मना रहा है, तब प्रत्येक भारतवासी की यह संकल्पशक्ति, भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए असीम विश्वास पैदा करती है।

श्री कोविंद ने कहा कि हमने एक साल से कम समय में कोविड रोधी टीकों की 150 करोड़ से भी ज्यादा खुराक लगाने का रिकॉर्ड पार किया। आज हम पूरी दुनिया में कोविड टीकों की सबसे ज्यादा खुराक देने वाले अग्रणी देशों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में 90 प्रतिशत से अधिक वयस्क नागरिकों को टीके की एक खुराक मिल चुकी है, जबकि 70 प्रतिशत से अधिक लोग दोनों खुराक ले चुके हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि अब तक देश में कुल आठ टीकों को आपात उपयोग के लिए स्वीकृति मिल चुकी है और भारत में बन रहे तीन टीकों को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की तरफ से आपात स्थिति में उपयोग की मंजूरी भी मिली है।

राष्ट्रपति ने कृषि क्षेत्र में हुए विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में देश की सतत सफलता और बढ़ते सामर्थ्य का सबसे बड़ा श्रेय, मैं, देश के छोटे किसानों को देना चाहता हूं। देश के 80 प्रतिशत किसान छोटे किसान ही हैं, जिनके हितों को मेरी सरकार ने हमेशा केंद्र में रखा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को एक लाख अस्सी हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस निवेश से कृषि क्षेत्र में आज बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि 'फसल बीमा योजना' में नए बदलावों का लाभ भी देश के छोटे किसानों को हुआ है। उन्होंने कहा कि इन बदलावों के बाद से अब तक आठ करोड़ से अधिक किसानों को मुआवजे के तौर पर एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी जा चुकी है।

> **देश के 80 प्रतिशत किसान छोटे किसान ही हैं, जिनके हितों को मेरी सरकार ने हमेशा केंद्र में रखा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को एक लाख अस्सी हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं**

रक्षा क्षेत्र की चर्चा करते राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हमारी सेनाओं की जरूरत का सामान भारत में ही विकसित हो तथा भारत में ही निर्मित हो। श्री कोविंद ने कहा कि 2020-21 में सैन्य बलों के आधुनिकीकरण के लिए जो भी स्वीकृतियां प्रदान की गईं, उनमें 87 प्रतिशत उत्पादों में 'मेक इन इंडिया' को प्राथमिकता दी गई। इसी प्रकार 2020-21 में 98 प्रतिशत उपकरणों से जुड़े अनुबंधों में 'मेक इन इंडिया' को प्राथमिकता दी गयी है।

उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर देश में रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण मेरी सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उज्ज्वला योजना की सफलता के हम सभी साक्षी हैं। मुद्रा योजना के माध्यम से हमारे देश की माताओं-बहनों की उद्यमिता और कौशल को बढ़ावा मिला है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' पहल के अनेक सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और स्कूलों में प्रवेश लेने वाली बेटियों की संख्या में उत्साहजनक वृद्धि हुई है।

उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि बेटे-बेटी को समानता का दर्जा देते हुए मेरी सरकार ने महिलाओं के विवाह के लिए न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर पुरुषों के समान 21 वर्ष करने का विधेयक भी संसद में प्रस्तुत किया है। ■

हमारे लिए राष्ट्र कोई सत्ता या सरकार की व्यवस्था नहीं है, बल्कि राष्ट्र एक जीवित आत्मा है: नरेन्द्र मोदी

भारत सरकार ने सुनिश्चित किया कि महामारी के बीच 80 करोड़ से अधिक भारतीयों को मुफ्त राशन मिले। यह हमारी प्रतिबद्धता है कि कोई भी भारतीय भूखा न रहे

गत सात फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के संसद में अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण से पहले लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि अपनी बात रखने से पहले मैं लता दीदी को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। अपनी आवाज के माध्यम से उन्होंने देश की एकता को मजबूत किया।

श्री मोदी ने नए संकल्प लेने और राष्ट्र निर्माण के कार्य में फिर से समर्पित होने के लिए वर्तमान कालखंड के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव, यह सोचने का प्रेरक अवसर है कि आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक नेतृत्व की भूमिका कैसे निभा सकता है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में विकास के कई कदम उठाए हैं। इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि कोरोना काल के बाद एक नई विश्व व्यवस्था तेजी से आकार ले रही है। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां हमें भारत के रूप में इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए।

लोकतंत्र की बात करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हम सब संस्कार, स्वभाव से, व्यवस्था से लोकतंत्र के प्रतिबद्ध लोग हैं और सदियों से हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि लेकिन ये भी सही है कि आलोचना जीवंत लोकतंत्र का एक आभूषण है] लेकिन अंध विरोध लोकतंत्र का अनादर है।

> **आजादी का अमृत महोत्सव, यह सोचने का प्रेरक अवसर है कि आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक नेतृत्व की भूमिका कैसे निभा सकता है**

श्री मोदी ने 100 साल पहले आई महामारी का भी जिक्र किया और कहा कि तब ज्यादातर मौतें भूख के कारण हुई थीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस महामारी में भूख से एक भी भारतीय की जान नहीं गई और इसके लिए जो उपाय किया गया, वह सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा उपायों में से एक है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने सुनिश्चित किया कि महामारी के बीच 80 करोड़ से अधिक भारतीयों को मुफ्त राशन मिले। यह हमारी प्रतिबद्धता है कि कोई भी भारतीय भूखा न रहे।

श्री मोदी ने 'आत्मनिर्भर भारत' की नई मानसिकता के बारे में भी बात की, जिसे आधुनिक नीतियों के जरिए आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने नए क्षेत्रों को खोलकर देश की प्रतिभाओं और युवाओं के सामर्थ्य का उपयोग करने पर प्रकाश डाला। हाल के समय में क्वालिटी यूनिकॉर्न में वृद्धि की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हम यह नहीं मानते कि केवल सरकारें सभी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। हम देश के लोगों और देश के युवाओं में विश्वास करते हैं। उदाहरण के लिए स्टार्ट-अप सेक्टर को ले लीजिए। स्टार्ट-अप की संख्या बढ़ी है और यह हमारे लोगों के सामर्थ्य को दिखाता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने युवाओं, वेल्थ क्रिएटर्स और उद्यमियों को डराने के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले सिर्फ 500 स्टार्टअप थे। पिछले 7 वर्षों में 60 हजार स्टार्टअप सामने आए और भारत के यूनिकॉर्न सेंचुरी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। स्टार्टअप्स के मामले में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।

उन्होंने कहा कि 'मेक इन इंडिया' का मजाक बनाना भारत की उद्यमिता, भारत के युवाओं और मीडिया उद्योग का अपमान है। उन्होंने यह भी कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना राष्ट्र सेवा का काम है।

श्री मोदी ने कहा कि हमारे लिए राष्ट्र कोई सत्ता या सरकार की व्यवस्था नहीं है, बल्कि राष्ट्र एक जीवित आत्मा है। उन्होंने पुराणों और महान कवि सुब्रमण्यम भारती का हवाला देते हुए भारत की व्यापक अवधारणा के बारे में विस्तार से बताया, जहां भारत को जीवित आत्मा के रूप में माना जाता है। प्रधानमंत्री ने अमृत काल की पावन अवधि में राजनीतिक दलों, नागरिकों और युवाओं से सकारात्मक भावना के साथ योगदान करने का आह्वान करते हुए अपनी बात पूरी की। ■

भविष्योन्मुखी बजट

रघुवर दास

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने बजट में राष्ट्र निर्माण के जिन प्रमुख पहलुओं पर सर्वाधिक बल दिया है, हमारे देश की आत्मनिर्भरता उनमें सर्वोपरि है। 'आत्मनिर्भर भारत' का नारा हम भले पिछले एक-दो वर्षों से सुनते आ रहे हो, पर यथार्थ में यह मोदी सरकार की नीतियों का प्रमुख केंद्र बिंदु रहा है। मोदी सरकार कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, आधारभूत संरचनाएं, तकनीकी संचार और स्वदेशी विनिमय, विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में भी लगातार स्वावलंबन के लिए प्रतिबद्ध रही है। उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार 'मेक इन इंडिया', आत्मनिर्भरता और वोकल फॉर लोकल, स्टार्टअप इंडिया जैसे माध्यम से न केवल अपने पूर्ण स्वावलंबन बल्कि दुनिया भी की जरूरतों को भी पूरा करने में मेक फॉर वर्ल्ड की ओर आगे बढ़ रही है।

वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट इन्हीं संकल्पों का बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है। देश की आत्मनिर्भरता और विकास की कसौटी पर मोदी सरकार की उपलब्धियां चमत्कृत करने वाली है। तमाम आंकड़े यह साबित करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था सभी कसौटियों पर आगे बढ़ रही है। निरंतर नये आयाम स्थापित हो रहे हैं।

मोदी सरकार ने न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम किया है, बल्कि अकर्मण्यता और कामचोरी पर भी कड़ा प्रभाव प्रहार किया है। काम करने वालों को वित्तीय-प्रशासनिक प्रोत्साहन मिल रहा है।

देश में उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार की व्यवस्था हो रही है। निर्यात की तमाम संभावनाओं को भी तलाशा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि प्रशासनिक जटिलताओं को भी दूर करने का सकारात्मक प्रयास हुआ है।

पूर्व की गैर भाजपा सरकार सरकारों में अब तक यही होता रहा कि लोकलुभावन और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने वाला बजट पेश किये जाते थे। उससे अर्थव्यवस्था कमजोर होती थी और राजकोषीय घाटा चरम पर होता था।

भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ सक्रिय है। दुनिया के लिए प्रेरित करने वाली है। भारत विरोधियों की इच्छाओं पर कुठाराघात करने वाली है, जबकि कोरोना काल में दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट और रुग्ण हो गई। अमेरिका और यूरोप तक की अर्थव्यवस्था लगभग चरमरा गई। भारत दुनिया की इतनी बड़ी आबादी को कोरोना में भी सक्रिय रखना और उनके लिए सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति को सक्रिय रखना बड़ा कठिन कार्य था। कोरोना बंदिशों के कारण उत्पादन कार्य प्रभावित था, आपूर्ति प्रक्रिया बाधित थी।

इसके बावजूद इस दौरान महंगाई लगभग नियंत्रित रही और आपूर्ति कार्य भी सक्रिय रहा।

कोई बजट तब महत्वपूर्ण होता है, जब उसके अंदर जरूरतमंदों और गरीब तबकों के लिए कल्याण की बातें होती है, विकास की बातें होती हैं। हमारे देश में गरीबी हटाओ अभियान का नारा वर्षों पूर्व में दिया गया था, पर आज तक गरीबी नहीं हटी। श्री नरेन्द्र मोदी के बजट और अन्य योजनाओं का विरोध करने वाली कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों से यह पूछा जाना चाहिए कि आज तक गरीबी क्यों नहीं हटी। उसके पीछे क्या कारण है। उन्होंने तो 50 वर्ष तक शासन किया था। लेकिन आज जब गरीबों के कल्याण के लिए व्यवस्था होती है, कोई मजबूत गरीबी उन्मूलन योजना लाती है, तो भी विपक्ष विरोध करता है। इस बजट में गरीबों के लिए जितनी धनराशि दी गई है, उतनी धनराशि कभी भी नहीं दी गई थी। गरीबों को विकास के लिए कोई एक नहीं बल्कि कई योजनाएं चल रही हैं।

सबसे बड़ी बात है कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी गांव में साफ पानी उपलब्ध नहीं है। गांव में अच्छी सड़कें न होना, साफ पानी उपलब्ध न होना चिंता की बात है। श्री नरेन्द्र मोदी ने यह बीड़ा उठाया है कि गांव में साफ पीने के पानी की समस्या को दूर करेंगे। देश का एक भी व्यक्ति प्यासा नहीं रहना चाहिए। ऐसा तब संभव होगा जब गांव में घर घर पानी की आपूर्ति के लिए पाइप लाइन बिछाई जाए। बजट में प्रावधान किया गया है कि 4 करोड़ लोगों के घरों में पानी के कनेक्शन दिए जाएंगे। पानी की आपूर्ति पर पहले 40 हजार करोड़ रुपये खर्च होते थे, पर इस बजट में 60 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे 3.8 करोड़ घरों तक साफ पानी उपलब्ध कराया जायेगा। इस राशि को डेढ़ गुना करना यह दर्शाता है कि श्री नरेन्द्र मोदी के लिए गांव को पानी पहुंचाने की योजना कितना महत्व रखती है। जल जीवन मिशन के तहत पहले से ही लगभग 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से पानी की आपूर्ति शुरू हो गई है।

नदी जोड़ो योजना फिर प्राथमिकता में आई है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने नदी जोड़ने की योजना शुरू की थी। नदी जोड़ने की योजना सिंचाई और पेयजल की समस्या दूर करने के लिए एक गेम चेंजर योजना थी। इससे बाढ़ पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है, लेकिन इसके बाद आई कांग्रेस सरकार ने इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब श्री नरेन्द्र मोदी ने फिर इस योजना को अमल में लाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में पानी की समस्या का समाधान होगा। देश की अन्य नदियों को भी जोड़ने की योजना है। इस योजना पर 44 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। नदियों को जोड़ने से पानी का प्रवाह लगातार रहेगा। किसानों के सूखे खेतों को पानी मिलेगा।

शेष पृष्ठ ३१ पर...

उत्तर प्रदेश में भाजपा की राजनीतिक यात्रा : एक नजर (भाग 2)

राम प्रसाद त्रिपाठी

प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयास किया था। इस कदम ने भारत की लोकतांत्रिक राजनीति को कई मायनों में प्रभावित किया, क्योंकि इस दौरान कई विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अतिरिक्त अभिव्यक्ति की आजादी और पत्र-पत्रिकाओं पर दबाव बनाने के लिए कठोर उपाय किये गये। आपातकाल 21 महीने तक चला और 1977 में चुनावों की घोषणा के साथ समाप्त हुआ। इसके साथ ही जनता पार्टी का गठन हुआ, जिसमें आपातकाल का विरोध करने वाले कई दलों के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस (ओ), स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनसंघ, लोक दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक छोटे से गुट, जिसका नेतृत्व जगजीवन राम कर रहे थे, इन सभी ने मिलकर इस गठबंधन का गठन किया था।

केंद्र में जनता पार्टी सरकार

आपातकाल, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक काला अध्याय था, ने केंद्र में जनता पार्टी की जीत का मार्ग प्रशस्त किया और श्री मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। इस सरकार में चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री थे और श्री जगजीवन राम रक्षा मंत्री बनें। भारतीय जनसंघ के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने और श्री लालकृष्ण आडवाणी सूचना और प्रसारण मंत्री बने। हालांकि, दो साल की छोटी अवधि में जनता पार्टी आपसी प्रतिद्वंद्विता, आंतरिक अंतर्विरोधों का शिकार हो गई और परिणामस्वरूप 19 जुलाई, 1979 को श्री मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया और केंद्र में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार गिर गई। इसके बाद तत्कालीन जनसंघ के नेताओं को 'दोहरी सदस्यता' की षड्यंत्र के कारण जनता पार्टी छोड़ने को मजबूर होना पड़ा।

भाजपा का जन्म और उसके बाद

06 अप्रैल, 1980 को जनसंघ के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया और श्री अटल बिहारी वाजपेयी नई पार्टी के पहले अध्यक्ष बनें। जून, 1980 में पार्टी के गठन के ठीक दो महीने बाद भाजपा ने उत्तर प्रदेश में चुनावी आगाज किया। इन चुनावों में पार्टी को 11 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस ने सरकार बनाई और श्री वीपी सिंह सीएम बनें।

वर्ष 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में चुनाव हुए और जो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद पहला आम चुनाव था और इन चुनावों में पार्टी को कुल 7.74 प्रतिशत मत हासिल हुए और भाजपा ने दो सीटें जीतीं।

उत्तर प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव 1985 में हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में अपनी पिछली प्रदर्शन में सुधार करते हुए 9.83 प्रतिशत मत हासिल किये और 16 सीटें जीतीं। लेकिन 1980 से 1988 तक उत्तर प्रदेश में राजनीतिक अनिश्चितता का दौर रहा और इस दौरान एक के बाद एक छः मुख्यमंत्री आए।

बोफोर्स घोटाला और जनता दल प्रयोग

1987 में बोफोर्स घोटाला सामने आया जिससे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की छवि को भारी क्षति हुई। शाहबानो मामले ने राजीव गांधी सरकार की अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीति को भी उजागर कर दिया। जनवरी 1988 में भाजपा ने राजीव गांधी के इस्तीफे और मध्यावधि चुनावों की घोषणा की मांग की। अगस्त, 1988 में नेशनल फ्रंट का गठन किया गया और श्री एनटी रामाराव इसके अध्यक्ष बने। साथ ही जनता दल का भी जन्म हुआ।

1989 तक प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी भ्रष्टाचार के आरोपों से बुरी तरह घिरे हुए थे और नवंबर में हुए आम चुनावों में वह मुश्किल से अपनी लोकसभा सीट को बचाने में कामयाब हुए। इसी के साथ उनकी सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ा। हालांकि, 141 सीटों के साथ जनता दल दूसरे सबसे बड़े घटक के रूप में उभरा और श्री वीपी सिंह के नेतृत्व में भाजपा (86 सीटों) और कम्युनिस्ट पार्टियों (44 सीटों) के समर्थन से गठबंधन ने बहुमत के जादुई आंकड़े को हासिल कर लिया, जिसने दिसंबर, 1989 में सत्ता संभाली थी। इन चुनावों ने भाजपा को 11.36 प्रतिशत मतों और 86 सीटों के साथ देश में एक प्रमुख राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित किया। इस चुनाव में बोफोर्स मुद्दे के साथ-साथ भाजपा ने 'सभी के लिए न्याय, किसी का तुष्टिकरण नहीं' के आदर्श वाक्य को अपना ध्येय बनाया।

आम चुनाव के साथ-साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी नवंबर, 1989 में हुए। इस चुनाव में अपनी पकड़ को और मजबूत करते हुए भाजपा ने 11.61 प्रतिशत मतों के साथ 57 सीटें जीतीं और राज्य में जनता दल सरकार को बाहर से समर्थन देने का निर्णय लिया। जनता दल ने 208 सीटें जीतीं और मुलायम सिंह यादव इसके मुखिया बनें। लेकिन श्री एनडी तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस के लिए यह चुनाव विनाशकारी साबित हुआ और यहां से कांग्रेस पार्टी के पतन की शुरुआत हुई और जो आज भी जारी है।

1980 के दशक के दौरान भाजपा ने उत्तर प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में अपनी पकड़ को मजबूत किया। भाजपा ने सितंबर, 1989 में श्री लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा शुरू की और यह यात्रा पार्टी के लिए महत्वपूर्ण

आंदोलन के तौर पर सामने आयी। इस यात्रा को पूरे देश में अभूतपूर्व जन समर्थन मिला।

यूपी में अपने दम पर पहली भाजपा सरकार बनी

1990 के दशक की शुरुआत के साथ उत्तर प्रदेश में राजनीतिक परिदृश्य में काफी बदलाव आया और भाजपा कार्यकर्ताओं के समर्पण और कड़ी मेहनत ने पार्टी को प्रदेश में जीत दिलाई। राज्य में 1991 में विधान सभा चुनाव हुए। जिसमें लोगों के भारी समर्थन के कारण भाजपा ने 33.30 प्रतिशत मत हासिल किये और 221 सीटें जीतीं। इसके साथ उत्तर प्रदेश में अपने बल पर पहली सरकार बनाईं और श्री कल्याण सिंह नए मुख्यमंत्री बने। 6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या में अवैध बाबरी ढांचे को विवादित कर दिया गया और इसके तुरंत बाद कल्याण सिंह सरकार को अलोकतांत्रिक रूप से बर्खास्त कर दिया गया और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया।

1996 में हुए अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 174 सीटें मिलीं। राष्ट्रपति शासन की अवधि के बाद भाजपा और बसपा ने अप्रैल 1997 में एक संक्षिप्त अवधि के लिए सरकार बनाई। वर्ष 2002 तक भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार राज्य में रहीं, जिनका श्री कल्याण सिंह, श्री राम प्रकाश गुप्ता और श्री राजनाथ सिंह ने नेतृत्व किया। इसके बाद दो मुख्य क्षेत्रीय दलों— बसपा और सपा ने 2017 तक राज्य में शासन किया। हालांकि, बसपा और सपा शासनकाल के दौरान भाई-भतीजावाद, राजनीतिक हिंसा, बिगड़ती कानून व्यवस्था, तुष्टिकरण की राजनीति, जातिवाद, भ्रष्टाचार और आतंकवाद ने प्रदेश और उसकी अर्थव्यवस्था को बीमारू राज्यों की श्रेणी में धकेल दिया।

2014 में भाजपा की अभूतपूर्व जीत

भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत हासिल की और पिछले दो आम चुनावों की तुलना में अधिक सीटें हासिल कीं, जिससे सीटों की संख्या बढ़कर 282 हो गयी, जो 1984 के चुनावों के बाद से किसी एक पार्टी द्वारा जीती गयी सबसे अधिक सीटें हैं। एनडीए ने लोकसभा की 336 सीटों पर जीत हासिल की। पार्टी ने वर्ष 2014 में 2009 की तुलना में 1.5 गुना अधिक मत प्रतिशत हासिल किया, इस हिसाब से देश में लगभग हर तीसरा वोट पार्टी को गया था। इस प्रचंड जीत के पीछे मुख्य कारण भाजपा और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेन्द्र मोदी के पक्ष चली लहर को माना जाता है। भाजपा क्षेत्रवाद, संप्रदायिक ध्रुवीकरण और जाति की सीमाओं को पार करने में सफल रही। भाजपा की सुनामी ने देश के विपक्षी दलों को झकझोरकर रख दिया और जिसमें कांग्रेस जैसे दलों का सफाया हो गया, जिसे लोकसभा चुनावों में केवल 44 सीटें मिली, जो कांग्रेस के हिसाब से अब तक की सबसे कम संख्या थी।

भाजपा की सुनामी का सबसे बड़ा प्रभाव उत्तर प्रदेश में महसूस किया गया, जहां पार्टी ने 80 में से 71 सीटों पर जीत हासिल की और पार्टी को 42.3 प्रतिशत वोट मिले। इन चुनावों में एनडीए को कुल 73 सीटें हासिल हुईं। यह 1984 के बाद से राज्य में किसी एक पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था।

अभूतपूर्व जीत के साथ भाजपा ने इतिहास रचा

तीन साल बाद वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। राज्य में भाजपा का 15 साल का के बाद भारी जीत के साथ शासन में आई। इन चुनावों में पार्टी को लगभग 40 प्रतिशत वोट मिले और पार्टी ने 312 सीटें जीतीं— जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में किसी पार्टी द्वारा जीती गई सीटों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। राज्य में भाजपा की आंधी कुछ इस तरह चली कि चुनावी पंडित, राजनीतिक विश्लेषक और मीडिया भी दंग रह गए। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और उनके गतिशील नेतृत्व में राज्य ने बहुआयामी विकास में नया इतिहास रचा।

क्रमशः... ■

पृष्ठ ३० का शेष...

फलस्वरूप उपज बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि होगी।

कोविड के समय उनकी स्थिति को देखते हुए किसानों के खाते में एमएसपी के 2.37 लाख करोड़ रुपये भी ट्रांसफर किये जायेंगे। कृषि उपकरण सस्ते होंगे। आनेवाले दिनों में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। किसानों तक तकनीक पहुंचाने की दिशा में भी काम करने की घोषणा हुई है। किसानों तक डिजिटल और हाईटेक तकनीक पहुंचाई जाएगी। कृषि क्षेत्र में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जायेगा।

हर व्यक्ति को छत उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्राथमिकता में है। पिछले 7 वर्षों में तीन करोड़ लोगों को घर बनाकर दिया गया है। अभावग्रस्त और जरूरतमंद लोगों को घर बनाने में धन की कमी नहीं होने दी जाएगी।

अभी तक सीमावर्ती इलाकों के विकास से की प्रक्रिया से बाहर थे। इसमें पिछली सरकारों का ध्यान नहीं था। सीमावर्ती गांव के लिए बिजली, सड़क, अस्पताल और शिक्षा आदि के क्षेत्र के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। सीमावर्ती गांवों में जब हमारी आधारभूत संरचनाएं मजबूत होगी, तब हम अपने दुश्मनों के नापाक इरादों को आसानी से ध्वस्त कर सकते हैं।

इस भविष्योन्मुखी बजट के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को देश की करोड़ों जनता की ओर से हार्दिक बधाई। ■

(लेखक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं)

युवाओं का बजट

विकास आनन्द

युवाशक्ति हमारे देश की आबादी का बड़ा हिस्सा है। इसलिए, वे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मोदी सरकार द्वारा संसद में पेश किया गया बजट रोजगार के विभिन्न अवसरों को सुनिश्चित करता है। 2022-23 के बजट में पूंजीगत व्यय में 35.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसे चालू वर्ष के 5.54 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2022-23 में 7.50 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह 2019-20 में खर्च की गई राशि के 2.2 गुना से अधिक है और जो 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.9 प्रतिशत होगा। कैपेक्स के लिए आवंटन के माध्यम से सरकार का इरादा तेजी से विकास करना और रोजगार के नये अवसर पैदा करना है। सरकार बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दे रही है, जो उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ रोजगार के नये अवसर भी सृजित करेगा। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि पीएम गति शक्ति (मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी) आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण के सात इंजन है, जिसमें सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग, और लॉजिस्टक ढांचे आदि शामिल है। यह सभी सात इंजन एक साथ अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे, जिनको ऊर्जा संचरण, आईटी संचार, पानी और सीवरेज एवं सामाजिक बुनियादी ढांचे की पूरक भूमिकाओं द्वारा समर्थित किया गया हैं। जिसको स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास—केंद्र सरकार का नजरिया, राज्य सरकारों के प्रयास और निजी क्षेत्र से बल मिलता है। इस पूरे पारिस्थिति तंत्र में युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार और उद्यमशीलता के अवसर पैदा होते हैं। एक्सप्रेसवे के लिए पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान 2022-23 तैयार किया जा रहा है और इसके लागू होने से नागरिकों और वस्तुओं के आवागमन तेज होने के साथ सुविधाजनक भी होगी।

2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर तक का विस्तार किया जाएगा और सार्वजनिक संसाधनों के लिए वित्तपोषण के नवीन तरीकों के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे। 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन को हासिल करने के लिए बजट में प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का दायरा बढ़ाकर 14 सेक्टरों तक किया गया है। इसमें 60 लाख नए रोजगार सृजित करने की क्षमता है और अगले 5 वर्षों के दौरान 30 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता है।

रेलवे में विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के मद्देनजर सरकार ने 'वन स्टेशन-वन प्रोडक्ट' की अवधारणा पर कार्य करना शुरू किया है। यह योजना स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रोत्साहित करने और लोकप्रिय बनाने में सहायक होगी। इसी तरह सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (CGTMSE) योजना युवाओं को आकर्षित करेगी। आवश्यक राशि के निवेश के साथ इस योजना को नया रूप दिया जाएगा। इससे सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 2 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण की सुविधा होगी और रोजगार के अवसरों का विस्तार होगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि एमएसएमई क्षेत्र को अधिक लचीला, प्रतिस्पर्धी एवं कुशल बनाने के लिए 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एमएसएमई प्रदर्शन (रैमप) कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल को आपस में जोड़ा जाएगा और उनका दायरा बढ़ाया जाएगा।

स्टार्टअप योजना, जो नये उद्यमियों को समर्पित है, को इस नए बजट में विभिन्न अनुप्रयोगों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें 'ड्रोन शक्ति' जैसे कार्यक्रमों को भी प्रमुखता दी गयी है। सभी राज्यों के चुनिंदा आईटीआई में कौशल विकास के लिए जरूरी कोर्स शुरू किए जाएंगे। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में कौशल को बढ़ावा देने और रचनात्मकता को पैदा करने के लिए विज्ञान और गणित में 750 आभासी प्रयोगशालाएं और 75 कौशल ई-प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।

बजट में एक डिजिटल विश्वविद्यालय की परिकल्पना की गई है जो देश भर के छात्रों को सुविधाजनक तरीके से सीखने का अनुभव प्रदान करने के साथ विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाली सार्वभौमिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करेगा।

बजट में एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक (एवीजीसी) प्रमोशन के लिए टास्क फोर्स की स्थापना का भी प्रस्ताव है, क्योंकि इस क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर पैदा किये जा सकते है। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने बजटीय भाषण में कहा कि दूरसंचार क्षेत्र और इसमें भी विशेष रूप से 5जी तकनीक रोजगार के नये अवसर प्रदान कर सकती है। उन्होंने कहा कि निजी दूरसंचार प्रदाताओं द्वारा 2022-23 के भीतर 5जी मोबाइल सेवाओं के रोलआउट की सुविधा के लिए 2022 में आवश्यक स्पेक्ट्रम नीलामी आयोजित की जाएगी। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अतंर्गत 5जी के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने के लिए एक विनिर्माण योजना शुरू की जाएगी।

रक्षा बजट के माध्यम से भी युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार सृजन की परिकल्पना की गई है। सरकार ने बजट के माध्यम से आयात को कम करने और सशस्त्र बलों के लिए उपकरणों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सरकार स्वदेशी निर्माताओं को रक्षा निर्माण में अधिक प्राथमिकता देने जा रही है। रक्षा बजट की पूंजीगत खरीद का 68 प्रतिशत 2022-23 में घरेलू उद्योग को आवंटित किया जाएगा, जो 2021-22 में 58 प्रतिशत था। इस आत्मनिर्भर रक्षा बजट में उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए रक्षा शोध और विकास के लिए बजट का 25 प्रतिशत रखा गया है। ये कदम एमएसएमई के लिए अधिक फायदेमंद होगा। ■

श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची 'स्टैच्यू ऑफ इक्वैलिटी' राष्ट्र को समर्पित

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पांच फरवरी को हैदराबाद में 'स्टैच्यू ऑफ इक्वैलिटी' राष्ट्र को समर्पित की। 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वैलिटी 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में स्थापित की गई है, जिन्होंने धार्मिक निष्ठा, जाति और पंथ सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता के विचार को बढ़ावा दिया था। इस अवसर पर तेलंगाना की राज्यपाल श्रीमती तमिलिसाई सौंदरराजन, केंद्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी भी उपस्थित थे।

समारोह में बोलते हुए श्री मोदी ने बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दीं और ऐसे पवित्र अवसर पर प्रतिमा स्थापित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जगद्गुरु श्री रामानुजाचार्य जी की इस भव्य विशाल मूर्ति के जरिए भारत मानवीय ऊर्जा और प्रेरणाओं को मूर्त रूप दे रहा है। रामानुजाचार्य जी की ये प्रतिमा उनके ज्ञान, वैराग्य और आदर्शों की प्रतीक है।

श्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया में जब सामाजिक सुधारों की बात होती है, प्रगतिशीलता की बात होती है, तो माना जाता है कि सुधार जड़ों से दूर जाकर होगा, लेकिन जब हम रामानुजाचार्य जी को देखते हैं, तो हमें अहसास होता है कि प्रगतिशीलता और प्राचीनता में कोई विरोध नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि सुधार के लिए अपनी जड़ों से दूर जाना पड़े, बल्कि जरूरी ये है कि हम अपनी असली जड़ों से जुड़ें, अपनी वास्तविक शक्ति से परिचित हों।

प्रधानमंत्री ने श्री रामानुजाचार्य को भारत की एकता और अखंडता की एक प्रदीप्त प्रेरणा बताया। उनका जन्म दक्षिण में हुआ, लेकिन उनका प्रभाव दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत पर है।

सरदार पटेल के हैदराबाद कनेक्शन का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अगर सरदार साहब की 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' देश में एकता की शपथ दोहरा रही है, तो रामानुजाचार्य जी की 'स्टैच्यू ऑफ इक्वैलिटी' समानता का संदेश दे रही है। यह एक राष्ट्र के रूप में भारत की विशेषता है।

यह प्रतिमा 'पंचधातु' से बनी है जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता शामिल है और यह दुनिया में बैठी अवस्था में सबसे ऊंची धातु की प्रतिमाओं में से एक है। यह 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है, जिसका नाम 'भद्र वेदी' है। इस परिसर में एक वैदिक डिजिटल पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र, प्राचीन भारतीय ग्रंथ, एक थिएटर, एक शैक्षिक दीर्घा है, जो श्री रामानुजाचार्य जी के कार्यों की जानकारी देते हैं। प्रतिमा की परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के श्री चिन्ना जीयर स्वामी ने की थी। ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बनें

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

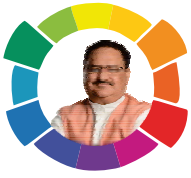

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय महिला आयोग के 30वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में भारत–मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

संसद के बजट सत्र से पूर्व नई दिल्ली में मीडिया को वक्तव्य देते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

करियप्पा ग्राउंड (नई दिल्ली) में आयोजित राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की रैली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

महात्मा गांधी पुण्यतिथि पर राजघाट, नई दिल्ली स्थित उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

मुंबई (महाराष्ट्र) में भारत रत्न, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश

अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध

लॉग इन करें:

www.kamalsandesh.org

राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh @KamalSandesh

kamal.sandesh KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2021-23
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2021-23

नई दिल्ली में 73वें गणतंत्र दिवस परेड की झलक

छायाकार: अजय कुमार सिंह